देश का Darpan News TV
FW FASTWAY
airtel
dish
Comming Soon
काम करने के लिए सम्पर्क करें

दैनिक समाचार पत्र
देश का दर्पण न्यूज
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली व महाराष्ट्र से प्रकाशित

अब आपके मोबाइल पर डिजिटिल अखबार
प्रदेश के ताजा समाचार
अपने लेख एवं समचार भेंजे
सम्पादक : उमेन्द्र राजपूत
7014997449, 9636058201
Email : deshkadarpannews@gmail.com
web.: www.deshkadarpannews.co

वर्ष-4, अंक-218
जयपुर, सोमवार , 20 जुलाई, 2026
मूल्य : 5.00 पेज:

हंगामेदार रहेगा मॉनसून सत्र, विपक्ष ने की केंद्र को घेरने की तैयारी

आज से मॉनसून सत्रः चढ़ावा चोरी से वांगचुक के मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, विपक्ष के वॉकआउट पर रिजिजू बोले- किसी के अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकते

नई दिल्ली/एजेंसी

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) को आमंत्रित करने के सरकार के फैसले का बचाव किया है। दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने अलग होकर एनसीपीआई का गठन किया है। इन बागी सांसदों को बैठक में बुलाए जाने के विरोध में कई विपक्षी दलों ने सांकेतिक वॉकआउट किया था। हालांकि, अपना विरोध दर्ज कराने के बाद वे वापस बैठक में लौट आए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में रिजिजू ने कहा कि सरकार ने पूरी तरह से संसदीय नियमों का पालन किया है। विपक्ष के विरोध पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एनसीपीआई ने लोकसभा अध्यक्ष से मान्यता देने का अनुरोध किया है। आप इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? सभी को आमंत्रित करना सरकार का कर्तव्य है।

मानसून सत्र के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए आठ बिल सूचीबद्ध किए गए हैं। इसके अलावा यदि कोई अन्य विधायी कार्य होता है, तो उसे संसदीय नियमों के अनुसार ही लिया जाएगा। रिजिजू ने सभी दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि संसदीय लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने बताया कि सरकार ने बैठक में विभिन्न दलों द्वारा रखे गए विचारों और सुझावों को गंभीरता से सुना है। विपक्ष के वॉकआउट पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने कहा कि यह केवल एक सांकेतिक कदम था। उन्हें उम्मीद है कि सभी विपक्षी दल समझदारी से काम लेंगे और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देंगे।

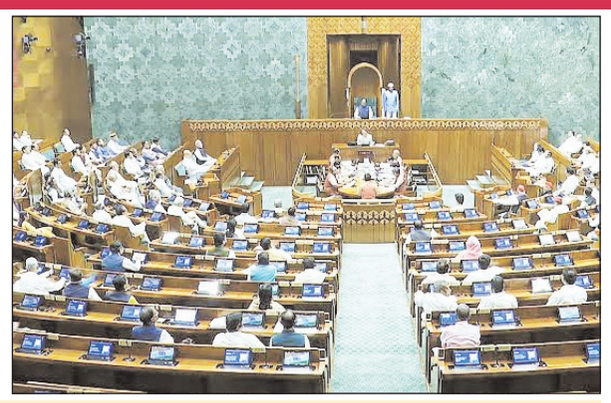

संसद में संख्या बल के आधार पर चर्चा होती है, किसी को वंचित नहीं किया जाता

संख्या बल के आधार पर चर्चा होती है, लेकिन किसी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

टीएमसी ने उठाए सवाल

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा एनसीपीआई बनाने वाले 20 बागी टीएमसी सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दिए जाने के बाद विपक्षी दलों ने यह वॉकआउट किया था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार के इस कदम पर तीखे सवाल उठाए। महुआ ने कहा कि स्पीकर ने अब तक इन बागी सांसदों के विलय को मंजूरी नहीं दी है और उनके खिलाफ अयोग्यता की याचिकाएं अभी भी लंबित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि टेबल ऑफिस द्वारा दी गई सूची में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 28 बताई गई है।

91वें संशोधन के बाद किसी अलग गुट के लिए कोई जगह नहीं बचती।

ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को किस आधार पर आमंत्रित किया? टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने भी इस निमंत्रण पर कड़ी आपत्ति जताई।

एनसीपीआई ने विपक्ष के सामने रखी बात

टीएमसी की आपत्तियों के बीच एनसीपीआई नेता सुदीप बंद्योपाध्याय ने बैठक में अपनी पार्टी की भागीदारी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पार्टी सरकार की ओर से आधिकारिक निमंत्रण मिलने के बाद ही इस बैठक में शामिल हुई है। गौरतलब है कि शनिवार को किरेन रिजिजू ने टीएमसी के बागी नेता सुदीप बंद्योपाध्याय और एनसीपीआई में शामिल हुए 19 अन्य लोकसभा सांसदों को मानसून सत्र से पहले होने वाली इस पारंपरिक सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया था।

मानसून सत्र में सरकार पेश करेगी पांच नए विधेयक

नई दिल्ली/एजेंसी

केंद्र सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में पांच नए विधेयक पेश करने जा रही है। इनमें आयकर और एमएसएमई सुधार, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। 18वीं लोकसभा के आठवें सत्र के दौरान सरकार आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026 और सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी।

इन दोनों विधेयकों के जरिए पहले जारी अध्यादेशों की जगह कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा सरकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 भी सदन में पेश करेगी। आयकर (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य पहले जारी अध्यादेश का स्थान लेना है।

न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव

इसे भारत के सॉवरेन डेट मार्केट को मजबूत करने, वैश्विक पूंजी निवेश आकर्षित करने और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए पेश किया जा रहा है। सरकारी प्रतिभूतियों से मिलने वाले ब्याज और पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 के जरिए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में मदद करना है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2026 का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और भरोसे पर आधारित नियामकीय व्यवस्था को बढ़ावा देना, भुगतान में देरी से जुड़े मामलों के समाधान की व्यवस्था को मजबूत करना तथा राज्यों को अधिक अधिकार देना है।

काशी भारत की सनातन चेतना का शाश्वत प्रकाश, यहाँ कण-कण में शिव का वासः रेखा

वाराणसी/एजेंसी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने जन्मदिन पर रविवार को यहां काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ और काशी के कोतवाल बाबा कालभैरव के दरबार में परिजनों के साथ विधिवत हाजिरी लगाई। दो दिवसीय काशी प्रवास पर आईं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोनों मंदिरों में विधि विधान से दर्शन पूजन के बाद दिल्ली सहित पूरे देश में सुख समृद्धि की कामना कीं। काशी के दोनों मंदिरों में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि आज, अपने जन्मदिन पर, मुझे शाश्वत, अविनाशी और मोक्ष प्रदान करने वाली काशी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ और काशी के कोतवाल श्री काल भैरव के पवित्र चरणों में दर्शन और पूजा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। काशी भारत की सनातन चेतना का शाश्वत प्रकाश है। यहाँ कण-कण में शिव का वास है, हर श्वास में भक्ति है और हर कदम पर आध्यात्मिकता का स्पंदन महसूस होता है। बाबा विश्वनाथ की कृपा और काल भैरव जी का संरक्षण अनादि काल से इस पवित्र भूमि और इसके भक्तों की शक्ति रहे हैं। मैं बाबा विश्वनाथ और श्री काल भैरव जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, सबको सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली का आशीर्वाद दें, और भारत निरंतर वैभव, गौरव और नई उपलब्धियों के शिखर को छूता रहे। इसके पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जन्मदिन पर वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बधाई दी है। उन्होंने अपने अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि "दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं। दिल्ली के विकास को बढ़ावा देने और लोगों के लिए 'जीवन को आसान बनाने' की दिशा में उनके प्रयास सराहनीय हैं। उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।"

मप्र कैबिनेट ने समान नागरिक विधेयक-2026 के प्रस्ताव को दी मंजूरी

भोपाल/एजेंसी

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में रविवार को भोपाल जिले के रियासतकालीन नगर जगदीशपुर में हुई कैबिनेट की बैठक में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी) विधेयक-2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। अब सोमवार, 20 जुलाई से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में इसे सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस फैसले पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों और प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार विधेयक को विधानसभा में पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि समानता भारतीय संस्कृति और मूल्यों का अभिन्न हिस्सा रही है। इसी भावना के अनुरूप सरकार ने यह कदम उठाया है। विधानसभा में विधेयक पेश होने के बाद उस पर चर्चा होगी और सदन की मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को सदन में पेश करने का फैसला लिया गया है। यूसीसी के जरिए राज्य में सभी को बराबरी का दर्जा मिल जाएगा, जिनमें 'राम' और 'रहीम' भी शामिल हैं।

यूसीसी पर नौ लाख 58 हजार सुझाव आएः सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू करने से पहले हम जनता बीच गए। दो महीने तक जनता से फीडबैक लिया। छह सदस्यीय कमेटी गठित की, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर तरह के प्रतिनिधि से राय ली गई। इस पर चर्चा के लिए सभी को बुलाया, लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं आए, क्योंकि उन्हें हर मौके पर हिंदू-मुस्लिम करना है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि यूसीसी पर नौ लाख 58 हजार सुझाव आए। इनमें 93.54% लोगों ने प्रदेश में इस कानून का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि 80 फीसदी मुस्लिम बहनों और 40 प्रतिशत मुस्लिम भाइयों ने भी एक समान कानून की मांग की है। यूसीसी के प्रस्ताव में प्रावधान किया गया है कि प्रदेश में विवाह सिर्फ एक ही मान्य होगा। दूसरा विवाह नहीं चलेगा। तलाक की प्रक्रिया भी कानूनी होगी। उत्तराधिकार का चयन कानून से होगा। महिला और पुरुष को समान अधिकार मिलेंगे। लिव-इन रिलेशन में एक महीने में पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसमें प्रावधान में है कि 21 साल का लड़का और 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की ही लिव इन में रह सकेगी। आदिवासी समाज को इस कानून में अपवाद रखा गया है। विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक अनिवार्य होगा। शादीशुदा व्यक्ति लिव-इन में रहता है तो 5 साल की सजा हो सकती है। भेद भाव पूर्ण प्रथाओं को रोकने का प्रयास किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ व राजौरी में बाढ़ व भूस्खलन के चलते 8 की मौत

राजौरी/एजेंसी

जम्मू-कश्मीर के पुंछ व राजौरी में बाढ़ व भूस्खलन के चलते 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लापता लोगों की तलाश व बचाव अभियान चलाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि दो सीमावर्ती ज़िलों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आई और जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। इस दौरान मोबाइल टावरों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते यहां का नेटवर्क भी बंद हो गया था, जिसे 5 घंटों के बाद बहाल किया गया है, लेकिन बिजली अभी तक बंद है। रात भर हुई लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन और अचानक बाढ़ आ गई, जिससे रिहायशी मकान मलबे में दब गए और कई परिवार मलबे के नीचे फंस गए। सबसे ज्यादा तबाही पुंछ जिले के सुराकोट के लोअर मुर्रा इलाके में हुई है।

मृतकों की पहचान नूर सफिया (59) पत्नी मोहम्मद लतीफ, सज्जाद अहमद (16) पुत्र मोहम्मद लतीफ, हकनवाज अहमद (10) पुत्र मोहम्मद लतीफ, शाहनवाज अहमद (10), पुत्र मोहम्मद लतीफ, खालिदा कौसर (25) पत्नी यासर इकबाल, सोफियान (2) पुत्र यासर इकबाल, बानो बी (60) पत्नी मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अकरम (7) पुत्र मोहम्मद लियाकत के रूप में हुई है। पुलिस, एसडीआरएफ, नागरिक प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवकों की बचाव टीमें उन छह लोगों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चला रही हैं, जो बह गए थे या मलबे के नीचे फंस गए थे और अभी भी लापता हैं।

नगालैंड में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन, आठ लोगों की मौत, 12 घायल

कोहिमा

नगालैंड के मोन जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच रविवार सुबह हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। डिफेंस कॉलोनी क्षेत्र में हुए इस हादसे में 10 से 15 मकान, जिनमें 13 घर पूरी तरह प्रभावित बताए जा रहे हैं, मलबे में दब गए।राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है, लेकिन लगातार बारिश, अस्थिर पहाड़ी ढलानों और तेज बहाव के कारण अभियान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को तत्काल अनुग्रह राशि और प्रभावित परिवारों को राहत सहायता देने की घोषणा की है।

अब तक चार शव निकाले गए

मोन के उपायुक्त वेन्येई कोन्याक ने कहा कि अब तक 4 शव बरामद किए गए हैं और चार अन्य लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हैं। उन्होंने बताया कि कई लोगों के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका है और उनकी तलाश जारी है। उन्होंने कहा, सबसे अधिक प्रभावित इलाके मोन टाउन और तिजित हैं।

हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के आमतला कार्यालय पर ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक

कोलकाता/एजेंसी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रविवार को विशेष अवकाशकालीन सुनवाई में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर संसदीय कार्यालय वाले आमतला स्थित भवन पर चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान पर तत्काल रोक लगा दी। न्यायालय ने अगली सुनवाई या अगले आदेश तक सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने यह अंतरिम आदेश लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में दक्षिण 24 परगना के अमतला स्थित संपत्ति पर की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई को "मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और अवैध" बताया गया है। मामले की तात्कालिकता को देखते हुए रविवार को विशेष रूप से इसकी सुनवाई की गई। लीप्स एंड बाउंड्स तथा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) की ओर से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया था। चूंकि संबंधित भवन से तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय भी संचालित होता है, इसलिए पार्टी को भी मामले में औपचारिक प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता तथा तृणमूल कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने पक्ष

प्रधानमंत्री ने बायोलॉजी और केमिस्ट्री ओलंपियाड के भारतीय मेडल विजेताओं को दी बधाई

नई दिल्ली/एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को लिथुआनिया के विल्नियस में आयोजित 37वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड और 58वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में पदक जीतने वाले भारतीय विद्यार्थियों को बधाई दी और उनकी उपलब्धि को देश के लिए गौरव का क्षण बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि विल्नियस में आयोजित 37वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में भारतीय टीम के सभी चार सदस्यों ने पदक हासिल किए हैं, जिसमें एक स्वर्ण पदक भी शामिल है। उन्होंने भव्य गुनवाल, सौमिल माइती, निशित कलानी और अनमोल कुमार को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी।

कोलकाता में देश के पहले 'शब्द संग्रहालय' का उद्घाटन, शाह बोले- भाषा हमारी संस्कृति और विरासत की पहचान

कोलकाता/एजेंसी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में भारत के पहले 'शब्द संग्रहालय' (म्यूजियम ऑफ वर्ड) का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा विकसित यह संग्रहालय देश की भाषाई विरासत, लिपियों और साहित्यिक परंपराओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि किसी भी देश की भाषा उसकी संस्कृति, इतिहास और विरासत की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि भाषा के माध्यम से किसी राष्ट्र की सभ्यता और उसके जीवन मूल्यों को समझा जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी मातृभाषा के साथ कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा सीखने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे भारत की सांस्कृतिक विविधता को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने पुस्तकालयों की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि किसी राष्ट्र का भविष्य केवल महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि कितने लोग पुस्तकालयों का उपयोग कर ज्ञान अर्जित करते हैं। पढ़ने की संस्कृति ही समाज को वैचारिक रूप से समृद्ध बनाती है। अमित शाह ने बंगाल की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि इस धरती ने देश को अनेक महान साहित्यकार, वैज्ञानिक, क्रांतिकारी और विद्वान दिए हैं। पश्चिम बंगाल एक बार फिर देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि वह पिछले नौ महीनों से पश्चिम बंगाल की प्रगति पर नजर रख रहे हैं और राज्य देश का "प्रकाश स्तंभ" बनता जा रहा है। शाह ने राज्य की भाजपा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में "सोनार बांग्ला" के निर्माण का संकल्प अवश्य पूरा होगा।

तेज रफ्तार मैजिक की चपेट में आए बुलेट सवार, दो युवकों की मौत

वाराणसी।
उत्तर प्रदेश में वाराणसी के राजातालाब थाना क्षेत्र अंतर्गत वीरभानपुर-ओदार स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप शनिवार देर शाम तेज रफ्तार मैजिक वाहन की टक्कर से बुलेट सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। जहां चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरे का इलाज जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार, वीरभानपुर निवासी जमाल (26), शाहिद (20) और मोहम्मद आमिर (20) शनिवार देर शाम बुलेट से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वे राजातालाब-जंसा मार्ग पर ओदार स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, सामने से आ रहे तेज रफ्तार मैजिक वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद तीनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

घटना की सूचना मिलते ही राजातालाब पुलिस चौकी प्रभारी राजेश मौर्य पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जमाल और शाहिद को मृत घोषित कर दिया, जबकि मोहम्मद आमिर की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही मृतकों और घायल युवक के परिजन अस्पताल पहुंच गए। दोनों युवकों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। रविवार को पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

राजातालाब पुलिस चौकी प्रभारी राजेश मौर्य ने बताया कि दुर्घटना के बाद मैजिक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस वाहन की पहचान कर उसकी तलाश में जुटी है तथा मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

जिलाधिकारी ने भलुअनी थाना का किया निरीक्षण, शिकायतों के निष्पक्ष निस्तारण के दिए निर्देश

देवरिया।
उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शनिवार देर रात भलुअनी थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विभिन्न अभिलेखों व रजिस्टरों की गहन जांच कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि थाने में आने वाले प्रत्येक फरियादी की शिकायत को गंभीरता और प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए। उन्होंने कहा कि सभी मामलों में निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी पीड़ित को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि थाने पर दर्ज होने वाले प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए, ताकि आमजन का पुलिस और प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

काशी भारत की सनातन चेतना का शाश्वत प्रकाश, यहाँ कण-कण में शिव का वास : रेखा गुप्ता

अपने जन्मदिन पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी

वाराणसी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने जन्मदिन पर रविवार को यहां काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ और काशी के कोतवाल बाबा कालभैरव के दरबार में परिजनों के साथ विधिवत हाजिरी लगाई। दो दिवसीय काशी प्रवास पर आईं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोनों मंदिरों में विधि विधान से दर्शन पूजन के बाद दिल्ली सहित पूरे देश में सुख समृद्धि की कामना कीं।

काशी के दोनों मंदिरों में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि आज, अपने जन्मदिन पर, मुझे शाश्वत, अविनाशी और मोक्ष प्रदान करने वाली काशी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ और काशी के कोतवाल श्री काल भैरव के पवित्र चरणों में दर्शन और पूजा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। काशी भारत की सनातन चेतना का शाश्वत प्रकाश है। यहाँ कण-कण में शिव का वास है, हर श्वास में भक्ति है और हर कदम पर आध्यात्मिकता का स्पंदन महसूस होता है। बाबा विश्वनाथ की कृपा और काल भैरव जी का संरक्षण अनादि काल से इस पवित्र भूमि और इसके भक्तों की शक्ति रहे हैं। मैं बाबा विश्वनाथ और श्री काल भैरव जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, सबको सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली का आशीर्वाद दें, और भारत निरंतर वैभव, गौरव और नई उपलब्धियों के शिखर को छूता रहे।

इसके पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जन्मदिन पर वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बधाई दी है। उन्होंने अपने अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि "दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं। दिल्ली के विकास को बढ़ावा देने और लोगों के लिए 'जीवन को आसान बनाने' की दिशा में उनके प्रयास सराहनीय हैं। उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं।"

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के दिए निर्देश

गोरखपुर।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक शनिवार को गोरखपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को मरीजों को बेहतर उपचार के साथ-साथ सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। दौरे की शुरूआत जिला अस्पताल के निरीक्षण से हुई। उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर भर्ती मरीजों से सीधे संवाद किया और उपचार, दवाओं की उपलब्धता तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में फीडबैक लिया। उन्होंने मरीजों से पूछा कि उन्हें समय पर इलाज मिल रहा है या नहीं तथा किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड में उमस और गर्मी की स्थिति को देखते हुए पाठक ने तत्काल एयर कंडीशनर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं के साथ-साथ स्वच्छ, सुरक्षित और आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराना भी स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को अस्पतालों में सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए।

जिलाधिकारी ने भलुअनी थाना का किया निरीक्षण, शिकायतों के निष्पक्ष निस्तारण के दिए निर्देश

देवरिया।
उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने शनिवार देर रात भलुअनी थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और विभिन्न अभिलेखों व रजिस्टरों की गहन जांच कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि थाने में आने वाले प्रत्येक फरियादी की शिकायत को गंभीरता और प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए। उन्होंने कहा कि सभी मामलों में निष्पक्ष, पारदर्शी और विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी पीड़ित को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

मंत्री अरविंद शर्मा ने झाड़ू लगाकर किया 76 दिवसीय वार्ड प्रवास कार्यक्रम की शुरूआत

वाराणसी।
वाराणसी में रविवार को सूरजकुंड वार्ड में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने 76 दिवसीय वार्ड प्रवास कार्यक्रम की शुरूआत किया। वाराणसी दक्षिणी विधानसभा में विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी की योजना से 76 दिवसीय वार्ड प्रवास के शुभारम्भ पर मुख्य अतिथि रहे मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने झाड़ू लगाया और स्थानीय लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया।

वार्ड प्रवास कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा कार्यकताओं के बीच मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन-जन को स्वच्छता के कार्य से जोड़ने के लिए झाड़ू उठाने का जो कार्य किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम स्वच्छता कार्य में जुटे हुए हैं। विश्व पटल पर आज वाराणसी की तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है, इसका एक प्रमुख कारण यहां का स्वच्छ वातावरण भी है।

विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी निर्वाचन क्षेत्र दक्षिणी विधानसभा में 76 दिवसीय वार्ड प्रवास का कार्यक्रम आज से प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित, 31 जुलाई तक करें ऑनलाइन नामांकन

चयनीत बच्चों के असाधारण कार्य के लिए छह विशिष्ट श्रेणियों में मिलेगा पुरस्कार

वाराणसी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने असाधारण प्रतिभा और उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2026' हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक एवं पात्र बच्चे स्वयं या अन्य पात्र माध्यमों के जरिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं।

जिला प्रोबेशन अधिकारी (महिला कल्याण विभाग) पंकज कुमार मिश्रा ने रविवार को बताया कि इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत बच्चों को उनके असाधारण योगदान के लिए छह श्रेणियों–वीरता, खेलकूद, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा कला एवं संस्कृति में सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को उनके असाधारण उपलब्धियों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।

उन्होंने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी में ऐसे बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने किसी नए उत्पाद, नवाचार, अनुसंधान, प्रोटोटाइप या वैज्ञानिक विचार का विकास किया हो। यदि वाराणसी जनपद के किसी बच्चे ने विज्ञान, रोबोटिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण तकनीक या किसी अन्य वैज्ञानिक क्षेत्र में उल्लेखनीय मॉडल, पेटेंट, शोध अथवा अभिनव कार्य किया है, तो वह इस पुरस्कार के लिए आवेदन करने का पात्र है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

बरेली में 1.30 करोड़ का प्रीकर्सर कैमिकल बरामद, चार तस्कर गिरफ्तार

बरेली ।
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) बरेली यूनिट ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार सक्रिय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 498.35 किलोग्राम एसिटिक एनहाइड्राइड प्रीकर्सर कैमिकल बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.30 करोड़ रुपये आंकी गई है। टीम ने दो वाहन, पांच मोबाइल फोन और 1,080 रुपये नकद भी बरामद किए हैं।

जिले में चलाए जा रहे अभियान के तहत 18 जुलाई को थाना शाही क्षेत्र के ग्राम जुनहाई बिजलीघर के सामने कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपितों में अमरोहा के चक मुस्तफापुर निवासी जोगेश उर्फ पिंकू, बदायूं के नदाईल निवासी वासिद, अमरोहा के हटऊआ निवासी तेजपाल सिंह और जोया निवासी अरुण कुमार शामिल हैं। बरामदगी के आधार पर थाना शाही में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पूछताछ में मुख्य आरोपित जोगेश ने बताया कि चारों लोग हरियाणा के मेवात से एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर आए थे। जोगेश और वासिद कार से, जबकि अरुण और तेजपाल पिकअप वाहन से गए थे। मेवात के एक व्यक्ति से कैमिकल लेकर उसे पिकअप में लोड किया गया था। इसे बदायूं के एक व्यक्ति को सौंपना था, जहां से पश्चिम बंगाल की एक पार्टी तक इसकी सप्लाई होनी थी। तस्करी से होने वाले मुनाफे को चारों आपस में बांट लेते थे।

एएनटीएफ बरेली यूनिट के प्रभारी उपनिरीक्षक विकास यादव ने बताया कि बरामद एसिटिक एनहाइड्राइड प्रीकर्सर कैमिकल का उपयोग हेरोइन जैसे मादक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। यह कार्रवाई नशा तस्करी की सप्लाई चेन पर बड़ी चोट है। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य तस्करों और सप्लायरों की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

वाराणसी के खोजवा में सामाजिक संगठन ने बदल दी प्राथमिक विद्यालय की सूरत

वाराणसी।
जिले में खोजवा स्थित प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट की सूरत बदलने के लिए सामाजिक संगठन कोरल ग्रुप ने तमाम प्रयास किए। वर्तमान समय में विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए नई बेंच उपलब्ध कराने के साथ ही दीवारों की मरम्मत, रंगरोगन, मैदान सफाई का कार्य कराया गया है।

प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट की प्रधानाचार्य अंजू दुबे ने बताया कि सामाजिक संगठनों के माध्यम या सहयोग से बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय में तमाम कार्यों को कराया जाता रहा है। इस बार कोरल ग्रुप ने सहयोग किया है और विद्यालय की सूरत बदली है। बच्चों के लिए नई बेंच उपलब्ध हो गई है। जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में सुविधा मिलेगी।

अंजू दुबे ने बताया कि कोरल ग्रुप ने एक माह पूर्व में विद्यालय परिवार से संपर्क किया था। इसके बाद उस समय की स्थिति के आधार पर बदलाव के लिए कार्यों को कराते हुए एक माह में सभी सहयोगी कार्यों को पूर्ण करा लिया।

कोरल ग्रुप के प्रबंध निदेशक खालिद ने कहा कि खोजवा के प्राथमिक विद्यालय में नए और आधुनिक फर्नीचर लगाए गए हैं। जिससे बच्चों को बैठाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जब बच्चे आराम से बैठ पाएंगे, तभी वह पढ़ने में अपना मन लगाएंगे। ग्रुप ने विद्यालय के विभिन्न आवश्यक कार्यों को कराया है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के भविष्य के लिए आगे भी हम अपना सहयोग देते रहेंगे।

पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को लेकर द्वारकाधीश मंदिर में हुआ पौधरोपण

औरैया।
उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में समाजसेवी संस्था एक विचित्र पहल सेवा समिति की ओर से चलाए जा रहे 'जीवनधारा पौधारोपण अभियान-5100' के तहत रविवार सुबह प्रार्थना नर्सिंग होम के समीप स्थित द्वारकाधीश मंदिर परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। अभियान के दौरान पौधों की देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी मंदिर के सेवादारों को सौंपी गई।

पौधरोपण के बाद आयोजित पर्यावरण गोष्ठी में समिति के संस्थापक आनंद नाथ गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि पेड़-पौधे विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराने की प्रेरणा देते हैं और मानव जीवन के लिए इनका महत्व सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण और उनकी नियमित देखभाल आवश्यक है। समिति शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, सार्वजनिक स्थलों, पार्कों और मार्गों पर ऑक्सीजन देने वाले दीर्घायु पौधों का रोपण कर रही है। साथ ही लोगों को उनकी पसंद के पौधे निःशुल्क भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मधुकामिनी, मालती बेल, हरसिंगार, बेलपत्र, चांदनी, गुड़हल, अशोक, चितवन और कदम सहित कई पौधे लगाए गए। गोष्ठी के अंत में उपस्थित लोगों ने अधिक से अधिक पौधरोपण करने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर धर्म नारायण अग्रवाल (लोली), अंजू अग्रवाल, डॉ. उपेंद्रनाथ मिश्रा, मनीष पुरवार (हीरू), तेज बहादुर वर्मा, राकेश गुप्ता, राम आसरे गुप्ता, संतोष पोरवाल, अनिल कुमार सोनी, संतोष कुशवाहा, शिवपाल, राजीव पोरवाल (रानू), आनंद नाथ गुप्ता एडवोकेट, सतीश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

मुठभेड़ में पांच अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार

बलिया।
जिले की पुलिस ने रविवार तड़के एक मुठभेड़ के बाद अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी का एक ट्रैक्टर, एक ट्रॉली, 11 मोटरसाइकिलें, दो पंपिंग सेट मोटर तथा चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) संजय वर्मा ने बताया कि रविवार तड़के करीब तीन बजे बैरिया से बिहार जाने वाले मार्ग पर वाहन चेकिंग की जा रही थी।

इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी की, तो मुख्य आरोपित हेमंत सिंह ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें हेमंत सिंह के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपित को तत्काल सीएचसी सोनबरसा भेजा गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने मौके से हेमंत सिंह के अलावा हर्ष राज सिंह उर्फ राज सिंह, दिनेश श्रीवास्तव, बिहार के सारण निवासी अनुज उपाध्याय उर्फ शिवम उपाध्याय तथा जयकुमार गोड़ उर्फ सन्टुल गोड़ को गिरफ्तार कर लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि गिरोह चोरी के वाहनों को बिहार ले जाकर बेचने की फिराक में था।

घायल आरोपित हेमंत सिंह को उपचार के लिए सीएचसी सोनबरसा भेजा गया। उसके पास से 315 बोर का एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

एएसपी ने बताया कि बरामद वाहनों और अन्य सामानों के संबंध में भी जांच की जा रही है तथा गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है।

बंगाल में बोले अमित शाह- आजादी के बाद ऐसा राजनीतिक बदलाव पहली बार हुआ

कोलकाता, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में अमूल बंगाल डेयरी परियोजना के तहत विश्व के सबसे बड़े दही उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन करते हुए पश्चिम बंगाल के राजनीतिक बदलाव को आजादी के बाद का सबसे बड़ा परिवर्तन बताया। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के बाद किसी भी राज्य में ऐसा राजनीतिक परिवर्तन देखने को नहीं मिला, जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ है।

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि एक समय पश्चिम बंगाल शिक्षा, संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश का मार्गदर्शक था। बंगाल ने देश को अनेक महान नेता, विचारक और स्वतंत्रता सेनानी दिए। अब राज्य फिर से विकास और समृद्धि के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि पहले तीन दशकों तक पश्चिम बंगाल पर वामपंथ की विदेशी विचारधारा का शासन रहा और उसके बाद 15 वर्षों तक राज्य भ्रष्ट और वैचारिक रूप से दिवालिया सरकार के अधीन रहा। उन्होंने कहा कि अब राज्य में आए राजनीतिक परिवर्तन से विकास की नई संभावनाएं खुली हैं।अमित शाह ने कहा कि लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से विकसित अमूल बंगाल डेयरी परियोजना राज्य की डेयरी सहकारिता के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। इस अत्याधुनिक संयंत्र में प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाएगा तथा 10 लाख किलोग्राम दही और अन्य दुग्ध उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही पैकेज्ड दूध, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, पनीर, घी, मिठाई और फ्लेवर्ड मिल्क का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा।उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 1.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनमें 30 हजार से अधिक महिला दुग्ध उत्पादक शामिल हैं। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, आधुनिक प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं का विस्तार होगा तथा पूर्वी भारत में डेयरी सहकारिता को नई मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 के तहत नवगठित डेयरी सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र सौंपे। उन्होंने बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को भी प्रमाण-पत्र प्रदान किए तथा सहकारी समितियों के पंजीकरण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए विकसित ई-आरसीएस पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में नए भंडारण गोदामों की आधारशिला रखी और दो नए गोदामों का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान राज्य में सदस्य आधारित परिवहन सेवाओं के विस्तार के लिए भारत टैक्सी और राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान भी हुआ।अपने तीन दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे के समापन पर अमित शाह ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ घुसपैठ रोकने, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं की सुरक्षा सहित विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर भी समीक्षा बैठकें कीं।

उन्होंने विश्वास जताया कि सहकारिता आधारित इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में श्वेत क्रांति को नई गति मिलेगी, किसानों की आय बढ़ेगी और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा बल मिलेगा।

कोलकाता में कानून-व्यवस्था की समीक्षा, अमित शाह ने महिला सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के दिए निर्देश

कोलकाता, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल, केंद्रीय गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिला सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा और सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में अमित शाह ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए राज्य में ह्यमहिला आउटरीच कार्यक्रमह्ल शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से ग्रामीण महिलाओं के साथ नियमित संवाद स्थापित कर उन्हें जागरूक और सशक्त बनाने को कहा। साथ ही स्पष्ट किया कि इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए राज्य सरकार सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क कर सकती है।आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य में विशेष जांच एजेंसी (एसआईए) के गठन की दिशा में आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। यह एजेंसी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तर्ज पर कार्य करेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पश्चिम बंगाल से जुड़े सभी आतंकवाद और गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम (यूएपीए) के मामलों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गहन समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए।

गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल पुलिस के आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने पुलिस बल के कैडर की समीक्षा कर राष्ट्रीय औसत के अनुरूप संख्या बढ़ाने, पुलिस जिलों का तर्कसंगत पुनर्गठन, सभी रिक्त पदों पर समयबद्ध भर्ती, प्रशिक्षण व्यवस्था की समीक्षा और नागरिक स्वयंसेवकों पर निर्भरता कम कर कांस्टेबलों की भर्ती को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।बैठक में पूर्व वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित सुरक्षा शिविरों के एक-तिहाई हिस्से को जन सुविधा केंद्रों में बदलने पर भी सहमति बनी, ताकि स्थानीय लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें। इसके अलावा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, मादक पदार्थों के खिलाफ नियमित समन्वय बैठकों का आयोजन और कोलकाता के लिए व्यापक बाढ़ प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के अंत में सभी संबंधित एजेंसियों को तय समय सीमा के भीतर प्राथमिकता वाले कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए।

कोलकाता में दस वर्षीय बालक कोविड संक्रमित, इलाज जारी

कोलकाता, कोलकाता के एक निजी अस्पताल में कोविड-19 से संक्रमित दस वर्षीय बालक को भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार, बालक की स्थिति स्थिर है तथा उसे चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। दक्षिण कोलकाता के गड़िया क्षेत्र निवासी बालक को शनिवार को तेज ज्वर, खांसी और सांस लेने में कठिनाई की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के लिए उसका स्वैब नमूना लिया गया, जिसकी रिपोर्ट कोविड-19 संक्रमित पाई गई। इसके बाद उसे अस्पताल के पृथक चिकित्सा कक्ष स्थित गहन चिकित्सा इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. साहेली दासगुप्ता ने बताया कि बालक पिछले तीन-चार दिनों से ज्वर, सर्दी और खांसी से पीड़ित था। एक्स-रे जांच में उसके दाहिने फेफड़े में निमोनिया के लक्षण पाए गए। विषाणु संबंधी जांच में सार्स-कोव-दो संक्रमण की पुष्टि हुई है। चूंकि कोरोना एक विषाणुजनित रोग है, इसलिए प्रतिजैविक औषधियों के स्थान पर उसे नेबुलाइजेशन सहित आवश्यक चिकित्सकीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। बालक की माता को भी पृथक रखा गया है तथा उनकी कोविड जांच कराने की तैयारी की जा रही है।

चिकित्सकों ने बताया कि बालक की स्थिति फिलहाल स्थिर है और उसके स्वास्थ्य पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है। हालांकि चिकित्सकों ने लोगों से घबराने की आवश्यकता नहीं होने की बात कही है।बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. साहेली दासगुप्ता ने बताया कि बालक पिछले तीन-चार दिनों से ज्वर, सर्दी और खांसी से पीड़ित था। एक्स-रे जांच में उसके दाहिने फेफड़े में निमोनिया के लक्षण पाए गए। विषाणु संबंधी जांच में सार्स-कोव-दो संक्रमण की पुष्टि हुई है। चूंकि कोरोना एक विषाणुजनित रोग है, इसलिए प्रतिजैविक औषधियों के स्थान पर उसे नेबुलाइजेशन सहित आवश्यक चिकित्सकीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। बालक की माता को भी पृथक रखा गया है तथा उनकी कोविड जांच कराने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है कि वर्षाकाल में बच्चों में ज्वर, सर्दी और खांसी के मामले सामान्य रूप से बढ़ जाते हैं। देश के कुछ हिस्सों में कोविड के नए मामले सामने आए हैं, किंतु अधिकांश संक्रमितों में हल्के लक्षण देखे जा रहे हैं और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता कम पड़ रही है। उल्लेखनीय है कि देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के बीच 12 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त चार संक्रमितों की मृत्यु भी हुई है।

पश्चिम मेदिनीपुर में सामाजिक, स्वास्थ्य और खेल गतिविधियों से भरपूर रही रविवार की छुट्टी

मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर जिले में रविवार को सामाजिक सेवा, संगठनात्मक प्रशिक्षण, खेलकूद तथा जनकल्याण से जुड़े विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संगठनों तथा बड़ी संख्या में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।

नारायणगढ़ के बेलदा स्थित ऑडिटोरियम सभागार में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान-2026' का आयोजन किया गया। शिविर में संगठन के कार्यकर्ताओं और युवाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद तथा अंत्योदय के विचारों से अवगत कराया गया। आयोजकों ने कहा कि युवाओं को आदर्शनिष्ठ, संगठित तथा समाजसेवा के कार्यों में अधिक सक्रिय बनाने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इसी दिन बेलदा रेल यात्री एवं नागरिक कल्याण समिति की ओर से गंगाधर अकादमी विद्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान, थैलेसीमिया जांच तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। नारायणगढ़ के बीडीओ सौमेन्द्रनाथ पाल ने स्वयं रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया, जबकि विधायक रमाप्रसाद गिरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

कोलकाता में देश के पहले शब्द संग्रहालय का उद्घाटन, अमित शाह बोले- भाषा हमारी संस्कृति और विरासत की पहचान

कोलकाता, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में भारत के पहले ह्यशब्द संग्रहालयह्ल (म्यूजियम ऑफ वर्ड) का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा विकसित यह संग्रहालय देश की भाषाई विरासत, लिपियों और साहित्यिक परंपराओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है।

उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि किसी भी देश की भाषा उसकी संस्कृति, इतिहास और विरासत की पहचान होती है। उन्होंने कहा कि भाषा के माध्यम से किसी राष्ट्र की सभ्यता और उसके जीवन मूल्यों को समझा जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी मातृभाषा के साथ कम से कम एक अन्य भारतीय भाषा सीखने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे भारत की सांस्कृतिक विविधता को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने पुस्तकालयों की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि किसी राष्ट्र का भविष्य केवल महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि कितने लोग पुस्तकालयों का उपयोग कर ज्ञान अर्जित करते हैं। पढ़ने की संस्कृति ही समाज को वैचारिक रूप से समृद्ध बनाती है।अमित शाह ने बंगाल की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि इस धरती ने देश को अनेक महान साहित्यकार, वैज्ञानिक, क्रांतिकारी और विद्वान दिए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल एक बार फिर देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि वह पिछले नौ महीनों से पश्चिम बंगाल की प्रगति पर नजर रख रहे हैं और राज्य देश का प्रकाश स्तंभ बनता जा रहा है। शाह ने राज्य की भाजपा सरकार की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला के निर्माण का संकल्प अवश्य पूरा होगा।

इस संग्रहालय के प्रथम चरण में भारतीय भाषाओं, लिपियों और साहित्य की विविधता को प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय को पारंपरिक प्रदर्शनी स्थल के बजाय एक आधुनिक अनुभवात्मक केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जहां डिजिटल डिस्प्ले, होलोग्राम, मोशन सेंसर और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से आगंतुक भारतीय भाषाओं के विकास की यात्रा को करीब से देख और महसूस कर सकते हैं।

आमतला में अभिषेक बनर्जी कार्यालय पर फिर चला बुलडोजर, हाई कोर्ट में सुनवाई के बीच कार्रवाई जारी

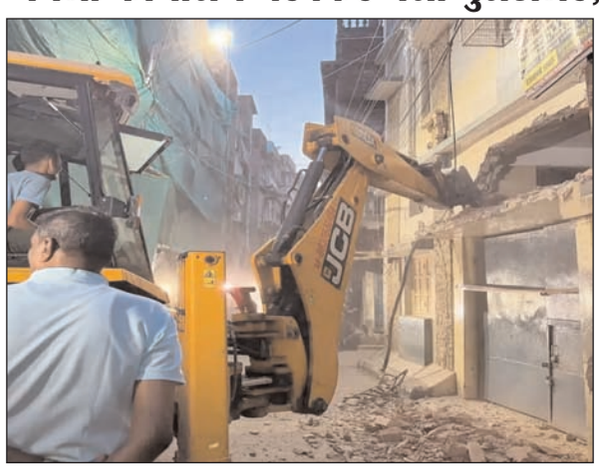

कोलकाता, दक्षिण 24 परगना के अमतला स्थित अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर प्रशासन ने रविवार को एक बार फिर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर दिया। पांच मंजिला इमारत को गिराने के लिए बुलडोजर और अन्य भारी मशीनों को मौके पर लगाया गया है। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और दमकल कर्मियों की भी तैनाती की गई है।

अभिषेक बनर्जी के इस कार्यालय को अवैध निर्माण बताते हुए प्रशासन ने शनिवार को भवन के एक हिस्से को ध्वस्त किया था। इसके बाद पूरी रात भवन के भीतर मौजूद सामान को हटाने का काम चलता रहा। रविवार दोपहर प्रशासनिक टीम दोबारा मौके पर पहुंची और शेष हिस्से को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी।

ध्वस्तीकरण को लेकर अभिषेक बनर्जी की संस्था लिप्स एंड बाउंड्स ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मामले की आपात सुनवाई चल रही है, लेकिन इसी दौरान प्रशासन ने भवन को गिराने की कार्रवाई जारी रखी।

प्रशासन ने रविवार को बुलडोजर के अलावा एयर कंप्रेसर, वाइब्रेटर और अन्य आधुनिक मशीनों का भी इस्तेमाल किया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, पूरे पांच मंजिला भवन को ध्वस्त किए जाने की योजना है। भवन के अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई और इसके खिलाफ अदालत में चल रही कानूनी लड़ाई अब राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बना गया है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के आमतला कार्यालय पर ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

कोलकाता, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रविवार को विशेष अवकाशकालीन सुनवाई में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर संसदीय कार्यालय वाले आमतला स्थित भवन पर चल रहे ध्वस्तीकरण अभियान पर तत्काल रोक लगा दी। न्यायालय ने अगली सुनवाई या अगले आदेश तक सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने यह अंतरिम आदेश लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में दक्षिण 24 परगना के अमतला स्थित संपत्ति पर की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई को "मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और अवैध" बताया गया है।

मामले की तात्कालिकता को देखते हुए रविवार को विशेष रूप से इसकी सुनवाई की गई। लीप्स एंड बाउंड्स तथा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) की ओर से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया था। चूंकि संबंधित भवन से तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय भी संचालित होता है, इसलिए पार्टी को भी मामले में औपचारिक प्रतिवादी बनाया गया है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर दत्ता तथा तृणमूल कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान किशोर दत्ता ने दलील दी कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वैधानिक प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए की गई। उन्होंने कहा कि नोटिस दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया और सुनवाई से पहले ही भवन को तोड़ना शुरू कर दिया गया।

उन्होंने अदालत को बताया कि संबंधित कानून के तहत किसी भी शिकायत पर पहले सुनवाई अधिकारी विचार करता है और उसकी अनुशंसा के बाद जिला परिषद के कार्यपालक अधिकारी अंतिम निर्णय लेते हैं। उनका कहना था कि संपत्ति के स्वामी को विधिवत नोटिस और सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य था, जो इस मामले में नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दावा किया गया कि ध्वस्तीकरण शुरू होने से पहले न तो कोई अंतिम आदेश और न ही शिकायत की प्रति उन्हें उपलब्ध कराई गई। दत्ता ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मौजूदगी में भवन को तोड़ा जा रहा है और अंदर रखा सामान भी नष्ट किया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की कि आवश्यक अभिलेख उसके समक्ष उपलब्ध नहीं ह।

पूर्व मंत्री तपन दासगुप्ता ने छोड़ी तृणमूल कांग्रेस, भाजपा में शामिल होने के दिए संकेत

हुगली, पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। हुगली जिले के सप्तग्राम से तीन बार विधायक और दो बार मंत्री रह चुके वरिष्ठ नेता तपन दासगुप्ता ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि वह सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो सकते हैं।

तपन दासगुप्ता मुख्यमंत्री रहीं ममता बनर्जी के चार दशक पुराने राजनीतिक सहयोगियों में रहे हैं। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक ममता बनर्जी के साथ राजनीतिक सफर तय किया। तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान वह दो बार मंत्री रहे। इसके अलावा उन्होंने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, हुगली जिला तृणमूल अध्यक्ष, फुरफुरा शरीफ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, पशुपालन विभाग तथा वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी निभाई।

हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद से वह पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे थे, हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कभी पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दिया। बाद में उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी असित मजूमदार को हुगली-श्रीरामपुर संगठनात्मक जिला तृणमूल अध्यक्ष बनाए जाने से उनकी नाराजगी और बढ़ गई। तृणमूल कांग्रेस छोड़ने की घोषणा करते हुए रविवार को तपन दासगुप्ता ने कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस के गठन के पहले दिन से पार्टी के साथ था और शुरूआती पांच नेताओं में मेरा नाम शामिल था। इतने वर्षों तक विभिन्न जिम्मेदारियां निभाने के बाद मुझे किनारे कर दिया गया। आज हुगली में धनियाखाली और चंडीतला को छोड़कर तृणमूल का जनाधार लगभग समाप्त हो चुका है। पार्टी बिखर गई है और जनता का विश्वास खो चुकी है। अब तृणमूल एक छोटी-सी पार्टी बनकर रह गई है। जब राजनीति व्यवसाय बन जाती है, तो किसी भी दल का यही हाल होता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वह राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहेंगे। साथ ही उन्होंने भविष्य में भाजपा में शामिल होने की संभावना जताया।

प्रत्येक सैन्य अभियान भविष्य के लिए नई सीख : पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे

कोलकाता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मजबूती को भारत के भविष्य की दो सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला बताते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत ने अपनी सामरिक क्षमता में उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए रक्षा तैयारियों को लगातार और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख कर कहा कि प्रत्येक सैन्य अभियान भविष्य के लिए नई सीख देता है इनसे मिले अनुभवों के आधार पर सशस्त्र बलों की रणनीति को और सशक्त बनाया जाना चाहिए।

कोलकाता के फेयरफील्ड बाय मैरियट में व्याना जियो-इकोनॉमिक फोरम (वीजीईएफ) की ओर से रविवार देर शाम आयोजित उद्घाटन राष्ट्रीय सेमिनार उभरती वैश्विक व्यवस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक लचीलापन : विकसित भारत की सामरिक प्राथमिकताएं विषय पर देश के प्रमुख सैन्य अधिकारियों, रणनीतिक विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और पूंजी बाजार से जुड़े विशेषज्ञों ने विस्तार से विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम में पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, ब्रिगेडियर आदित्य सहाय सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक, उद्योगपति और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ उपस्थित रहे।उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्ध बहुआयामी होंगे, जिनमें जमीन, समुद्र और वायु के साथ-साथ साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इसलिए भारतीय सशस्त्र बलों को इन सभी क्षेत्रों में एकीकृत क्षमता विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा कि सैनिकों के प्रशिक्षण, आधुनिक हथियारों की उपलब्धता, तकनीकी दक्षता और तेज निर्णय लेने की क्षमता पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके।

पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि आधुनिक युद्ध में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है लेकिन एक सैनिक की सबसे बड़ी ताकत आज भी उसका अनुशासन, राष्ट्र के प्रति समर्पण, ईमानदारी, साहस और कर्तव्यनिष्ठा है। ये ऐसे मूल्य हैं जो किसी भी दौर में नहीं बदलते और भारतीय सेना की पहचान भी यही है।सेमिनार के समापन सत्र में जनरल मनोज पांडे ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, साइबर युद्ध, अंतरिक्ष आधारित निगरानी प्रणाली और अत्याधुनिक हथियारों ने युद्ध की पूरी प्रकृति बदल दी है।

कार पार्किंग के समय हादसा, टक्कर लगने से व्यक्ति की मौत

हुगली, हुगली जिले के चंदननगर के श्रीपल्ली इलाके में शनिवार शाम कार पार्किंग के दौरान हुए एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कार मालिक को पार्किंग करना सिखाते समय वाहन की चपेट में आने से बुद्धदेव सरकार की जान चली गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने कार चालक शैबाल साहा को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बुद्धदेव सरकार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी शैबाल साहा की कार चलाते थे। उन्होंने शैबाल साहा को पहले ही कार चलाना सिखा दिया था और अब उन्हें सही तरीके से कार पार्क करना सिखा रहे थे।

शनिवार शाम दोनों काम समाप्त कर चंदननगर स्थित सुपरस्टिच प्लाजा नामक आवासीय परिसर पहुंचे, जहां कार को गैरेज में पार्क किया जाना था। उस समय कार शैबाल साहा चला रहे थे, जबकि बुद्धदेव सरकार बाहर खड़े होकर उन्हें पार्किंग के संबंध में निर्देश दे रहे थे। इसी दौरान अचानक कार आगे बढ़ी और सीधे बुद्धदेव को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े।

स्थानीय लोगों ने तत्काल उन्हें टोटो से चंदननगर महकमा अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शैबाल साहा को हिरासत में ले लिया है तथा दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर चंदननगर थाने ले जाकर जांच शुरू कर दी है।

इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की आशंका प्रभावित किसानों से मिले सांसद संजय सिंह संसद में उठाएंगे आवाज

डॉ उदय शंकर भगत वाराणसी
' राजा तालाब अदमा और अमिनी सहित कुल 13 गांवों के किसानों पर इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के लिए अपनी बेहद उपजाऊ कृषि भूमि छिन जाने का खतरा मंडरा रहा है राजातालाब तहसील अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की इस गंभीर आशंका से परेशान और आक्रोशित किसानों की सुध लेने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बरियासनपुर गांव पहुंचे उन्होंने प्रभावित किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं और चिंताओं को सुना।इस मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एलान किया है कि वे प्रभावित किसानों की इस जायज लड़ाई को देश की सबसे बड़ी पंचायत, यानी संसद भवन नई दिल्ली तक ले जाएंगे और उनकी आवाज को दबने नहीं देंगे प्रभावित ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि

अदमा व अमिनी सहीत जिन 13 गांवों की जमीन को इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित करने की तैयारी चल रही है वह बेहद उपजाऊ कृषि योग्य भूमि है। इसी जमीन पर खेती कर पीढ़ियों से उनके परिवारों का भरण-पोषण हो रहा है। किसानों ने आशंका जताई है कि यदि सरकार ने इस बहुफसली और उपजाऊ जमीन का जबरन अधिग्रहण किया, तो सैकड़ों परिवार दाने-दाने को मोहताज हो जाएंगे और उनका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा।

किसानों से संवाद के दौरान सांसद संजय सिंह ने उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर अन्नदाताओं की उपजाऊ जमीन छीनना पूरी तरह से गलत है। सांसद ने आश्वस्त किया कि वे इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद करेंगे किसानों के हक में लगातार आवाज उठाने वाले समाजसेवी सूबेदार यादव ने इस मामले को लेकर कहा कि अदमा अमिनी 13 गांवों यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि किसानों की आजीविका है हम इस सरकार मांग करेंगे कि वह किसानों के हितों को ताक पर रखकर कोई भी एकतरफा फैसला न ले

सांसद संजय सिंह के दौरे के बाद 13 गांवों के किसानों में एकजुटता और बढ़ गई है किसानों का साफ कहना है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी उपजाऊ भूमि को उद्योगपतियों के हवाले नहीं होने देंगे।

काशी को 25 हजार करोड़ देने पर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकताओं ने रैली निकालकर आभार जताया

डॉ उदय शंकर भगत वाराणसी मिजार्मुराद सेवापुरी विधानसभा के कछवांरोड चौराहे पर शनिवार की शाम भाजपा जिलाध्यक्ष राम शकल पटेल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकताओं ने रैली निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी को 25 हजार करोड़ की गंगा-वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की सौगात दिये वही कछवा रोड रूपापुर मिजार्मुराद लालपुर इत्यादि क्षेत्र के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए पैदल बैनर तले पद यात्रा निकालकर हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाते हुए बाजारवासियों को योजनाओं के बारे में बारी-बारी बताकर आभार व्यक्त किया।जिलाध्यक्ष ने कहां की काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी में एक से बढ़कर एक विकास कार्य किया जा रहा है बाहर से आज हर कोई काशी आने के लिए तैयार रहता है हम सभी उनका

धन्यवाद व्यक्त करते है इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव सिंह गौतम जिला उपाध्यक्ष अरविंद प्रधान जिला मंत्री अश्वनी पांडेय सेवापुरी मंडल अध्यक्ष अभिषेक दूबे ग्राम प्रधान मंडल उपाध्यक्ष सुनील कुमार बिन्द उमाशंकर पटेल अभिषेक त्रिपाठी सुमित मंडल महामंत्री दीपक सिंह ऋषि सिंह मनोज विश्वकर्मा गुड्डू सिंह ओमप्रकाश पटेल आतिश कुमार बिन्द अंकुश दूबे संदीप केशरी समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

जयसिंहपुरा खोर पुलिस थाना मे नवनियुक्त थाना अधिकारी रघुवीर सिंह जी का किया स्वागत

देश का दर्पण न्यूज जयपुर, संयुक्त विकास सेवा समिति जयसिंहपुरा खोर के तत्वावधान में समिति के सदस्यों,पदाधिकारियों द्वारा नवनियुक्त जयसिंहपुरा खोर थाना के थानाअधिकारी श्री रघुवीर सिंह जी का दुपट्टा माला पहनाकर किया गया स्वागत संयुक्त विकास समिति के अध्यक्ष जयपाल सिंह वधावन,महासचिव दिनेश विजय वर्गीय,मीडिया प्रभारी दुलीचंद शर्मा, व विजय टींक़र,महेंद्र बंसल,रिंकू जांगिड़,सुरेंद्र सोनी, व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए रहे।

सभी ने नवनियुक्त थानाधिकारी श्री रघुवीर सिंह जी का दुपट्टा व माला पहनाकर भव्य स्वागत कर शुभ कामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। थानाधिकारी श्री रघुवीर सिंह जी ने समिति के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया व समिति के सभी लोगों को आश्वासन दिया कि कही पर भी कोई भी गलत कार्य नशा का व्यापार या कोई भी नियम विरुद्ध कार्य कार्य करता है तो आप लोग इसकी सूचना दे ऐसे कार्य करने वालों के प्रति शख्त से शख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिससे आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहे।

दाधीच समाज मुक्ति धाम में किया वृक्षारोपण

मेड़ता सिटी(लक्ष्मीनारायण वैष्णव)/ पर्यावरण एकं जिम्मेदारी के तहत रविवार को श्री दाधीच समाज सेवा समिति व दाधीच नवयुवक मंडल मेड़ता सिटी के संयुक्त तत्वावधान में डांगोलाई रोड़ पर स्थित दाधीच समाज के स्वर्गाश्रम (मुक्ति धाम) में वृक्षारोपण किया गया वहीं पुराने पेड़ों की देखभाल व साफ सफाई की गई। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर दाधीच, उपाध्यक्ष प्रदीप दाधीच, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार तिवाड़ी, एडवोकेट मुकेश व्यास, नन्दु व्यास, नवयुवक मंडल के पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार व्यास, धीरज व्यास, इन्द्र चन्द तिवाड़ी, सहित अनेक समाज बन्धुओं ने वृक्षारोपण हेतु श्रमदान किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर दाधीच ने पर्यावरण को समाज की जिम्मेदारी बताते हुए पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन एवं पर्यावरण समृद्धि पर जोर दिया तथा श्रमदान करने वाले सभी समाज बन्धुओं के प्रति आभार प्रकट किया।

थर्मस चोरी की शिकायत पर छात्र को स्कूल से निकाला, कार्रवाई की मांग

(बिहार वैशाली) पातेपुर संवाददाता रंजीत कुमार
पातेपुर बलिगांव निवासी संतोष कुमार सिंह ने अपने पुत्र के साथ कथित दुर्व्यवहार एवं निजी विद्यालय की मनमानी को लेकर जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि उनका आठ वर्षीय पुत्र गौतम कुमार स्टार ग्लोरी एके-डमी में नर्सरी कक्षा का छात्र है। 15 जुलाई को विद्यालय से छुट्टी के बाद घर पहुंचने पर वह रो रहा था। पूछने पर उसने बताया कि विद्यालय में उसका थर्मस चोरी हो गया। आरोप है कि शिक्षक से शिकायत करने पर बच्चे को डांटकर भगा दिया गया और अभिभावक को बुलाने की बात कही गई।

आवेदन में कहा गया है कि शिकायत लेकर जब वह विद्यालय पहुंचे तो प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाने का अनुरोध किया, लेकिन कथित रूप से इससे भी इनकार कर दिया गया। अभिभावक का आरोप है कि उन्हें प्रभाव और पहुंच का हवाला देकर शिकायत नहीं करने की नसीहत दी गई।

संतोष कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि अगले दिन जब वह अपने पुत्र को विद्यालय छोड़ने पहुंचे तो विद्यालय प्रबंधन ने बच्चे को कक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया। आरोप है कि 1600 रुपये जमा करने के बाद ही थर्मस उपलब्ध कराने और कक्षा में बैठने देने की बात कही गई। विरोध करने पर कथित रूप से धमकी दी गई कि शिकायत करने पर उनके पुत्र का कहीं भी नामांकन नहीं होने दिया जाएगा।

अभिभावक ने आवेदन में कहा है कि इस घटना से उनका पुत्र मानसिक रूप से आहत है तथा पूरे मामले से परिवार की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है। उन्होंने डीएम, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

सोजत मे विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल का सेवा सप्ताह के तहत दो दिवसीय स्वास्थ्य शिविर संपन्न

अकरम खान, सोजत। विश्व हिंदू परिषद-बजरंग दल, जिला सोजत द्वारा सेवा सप्ताह के अंतर्गत दो दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हवाई पट्टी के पीछे स्थित खंडों वाली बस्ती एवं गाडोलिया लोहार कॉलोनी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर में क्षेत्र के नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सकीय परामर्श तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श और दवाइयों संबंधी मार्गदर्शन दिया। इस दौरान डॉ. ज्योति, डॉ. सलीम, भूपेन्द्र, सिद्धार्थ सिंह, देवेन्द्र वैष्णव, वर्षा, जयश्री, निखिल, मानवेन्द्र सिंह एवं रविन्द्र ने अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए क्षेत्रवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधिवक्ता आनंद भाटी ने कहा कि बजरंग दल का सेवा सप्ताह समाज के प्रत्येक वर्ग तक सेवा और सहयोग पहुंचाने का अभियान है। उन्होंने सभी चिकित्सकों, स्वयंसेवकों एवं सहयोगकताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य निरंतर जारी रखने का संकल्प दोहराया।

इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री मानवेन्द्र भाटी, सेवा प्रमुख रणजीत सिंह राजपुरोहित, कार्यक्रम संयोजक कमलेश पंवार, अनिल, तनुज, योगेश, विधि प्रकोष्ठ प्रमुख घेवरराम गहलोत, युवराज मालवीय, जोगेश जोशी(लक्की), मोनिका मालवीय, धीरज, सुनील तथा अभिषेक सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने शिविर की व्यवस्थाओं को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई।

बूढ़ा अमरनाथ के लिये यात्रा 15 अगस्त को धौलपुर से होगी रवाना

देश का दर्पण न्यूज,धौलपुर (धर्मेन्द्र बिधौलिया) विश्व हिंदू परिषद की जिला बैठक रविवार को गंगा बाई की बगीची में महंत हनुमानदास जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक का शुभारंभ भगवान श्रीराम एवं भारत माता के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

बैठक में जिला मंत्री वैद्य गिरीश ने जिले में दायित्वान कार्यकताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की तथा संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा की। आगामी प्रांत बैठक 25 एवं 26 जुलाई को अलवर में आयोजित होने की जानकारी कार्यकताओं को दी गई।

जिला सह मंत्री मनोज सोनी ने बताया कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 15 अगस्त 2026 को धौलपुर से प्रस्थान करेगी तथा 16 अगस्त को जम्मू से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होगा। उन्होंने कार्यकताओं से यात्रा में अधिक से अधिक सहभागिता का आह्वान किया।

राम शमार्ने बताया कि साधु-संतों के आह्वान पर चलाए जा रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। प्रांत पदाधिकारियों के निर्देशानुसार विश्व हिंदू परिषद द्वारा अभियान में पूर्ण सहयोग करने का निर्णय लिया गया। अभियान के तहत गांव-गांव और घर-घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाने की जिम्मेदारी कार्यकताओं को सौंपी गई।

बैठक में आगामी 27 जुलाई को अधिक से अधिक कार्यकताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए हस्ताक्षरित प्रपत्र जिला कलेक्टर को सौंपने को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए ग

इस अवसर पर जिला मंत्री गिरीश वैद्य, जिला सह मंत्री मनोज सोनी, बजरंग दल जिला संयोजक चंद्रप्रताप धाकरे, जिला सह संयोजक नरेश कुमार, संपर्क प्रमुख राम शर्मा, सत्संग प्रमुख अर्चना भार्गव, प्रखंड मंत्री अशोक कुलश्रेष्ठ, विजेंद्र माहौर, विकास शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दर्द से परेशान मरीजों के लिए एडवांस न्यूरोस्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर में स्पाइन एंडोस्कोपी का नि:शुल्क शिविर संपन्न

डॉ उदय शंकर भगत वाराणसी । लंबे समय से कमर दर्द साइटिका स्लिप डिस्क पैर में झनझनाहट तथा रीढ़ की नस दबने जैसी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए एडवांस न्यूरोस्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर मंडुआडीह वाराणसी में रविवार को स्पाइन एंडोस्कोपी का निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया शिविर में बड़ी संख्या में वाराणसी सहित आसपास के जनपदों से आए मरीजों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लेकर लाभ उठाया शिविर का संचालन प्रसिद्ध स्पाइन विशेषज्ञ डॉ. एस. के. जायसवाल के मार्गदर्शन में किया गया उन्होंने बताया कि पिछले दस वर्षों में एंडोस्कोपी दूरबीन तकनीक के माध्यम से हजारों स्पाइन मरीजों का सफल उपचार किया जा चुका है। यह आधुनिक तकनीक कम समय में बेहतर राहत देने के साथ-साथ पारंपरिक सर्जरी की जटिलताओं को भी काफी हद तक कम करती है

शिविर के दौरान स्पाइन एवं पेन मैनेजमेंट विशेषज्ञों की टीम ने मरीजों की निःशुल्क जांच परामर्श और आवश्यक उपचार संबंधी सुझाव दिए चिकित्सकों ने प्रत्येक मरीज की समस्या का विस्तार से परीक्षण कर उचित उपचार एवं जीवनशैली से जुड़े आवश्यक सुझाव भी प्रदान किए डॉ. एस. के. जायसवाल ने कहा कि यह शिविर विशेष रूप से उन मरीजों के लिए लाभकारी रहा जो लंबे समय से रीढ़ संबंधी दर्द से परेशान हैं और सर्जरी से बचते हुए आधुनिक उपचार विकल्प अपनाना चाहते हैं उन्होंने लोगों से अपील की कि शिविर में बताए गए स्वास्थ्य संबंधी सुझावों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं तथा रीढ़ से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें। समय रहते विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेने से गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है।

फुलेरा थाने में सीएलजी, सुरक्षा सखी,पुलिस मित्र एवं व्यापारियों की बैठक आयोजित

संवाददाता सुरेन्द्र कुमार सोनी
थाना फुलेरा में रविवार सायं 5 बजे सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्रों एवं व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप पुलिस अधीक्षक, सांभर लेक श्री मुकेश जोशी ने की, जबकि आयोजन थानाधिकारी राजेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में संपन्न हुआ। बैठक में श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज ,जयपुर श्री राहुल प्रकाश के निदेर्शानुसार क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा पुलिस और आमजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने व्यापारियों, सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखी एवं पुलिस मित्रों से अपने-अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि या घटना की तत्काल सूचना पुलिस को देने का आह्वान किया। उप पुलिस अधीक्षक मुकेश जोशी ने कहा कि अपराध नियंत्रण में आमजन की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिस और नागरिकों के सहयोग से ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सकता है।

बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने पुलिस को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया।

भा ज पा महानगर एवं जिला की विधानसभाओं के मंडल अध्यक्षों व महामंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

डॉ उदय शंकर भगत वाराणसी ' महानगर कार्यालय गुलाब बाग में आगामी 22 जुलाई को होने वाले बूथ सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने और संगठनात्मक तैयारियों को धार देने के लिए महानगर एवं जिला की विधानसभाओं के मंडल अध्यक्षों एवं महामंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक चुनाव की नींव हमारा बूथ कार्यकर्ता होता है बूथ सम्मेलन के माध्यम से हमें संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करना है उन्होंने सभी पदाधिकारियों को पूरी ऊर्जा के साथ तैयारियों में जुटने का आह्वान करते हुए कहा महानगर एवं जिला के विधानसभाओं के अंतर्गत आने वाले सभी बूथों पर कार्यकताओं की सक्रियता और जनसंपर्क अभियान को तेज किया जाए मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में प्रवास कर सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करें ताकि यह आयोजन पूरी तरह सफल हो सके सभी पदाधिकारियों ने बूथ सम्मेलन को सफल बनाने और संगठन के दिशा-निदेर्शों का पूरी निष्ठा से पालन करने का संकल्प लिया बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष रामसकल पटेल राहुलसिंह जगदीश त्रिपाठी मधुकर चित्रांश अभिषेक मिश्रा।

अशोक जाटव आलोक श्रीवास्तव साधना वेदांती प्रवीण सिंह गौतम जेपी दुबे सुरेंद्र पटेल प्रीति सिंह मनोज सोनकर पीयूष भट्टाचार्य आदि रहे।

पीपलू थानाधिकारी सामरिया का बजरी माफिया पर कड़ा प्रहार, अवैध बजरी परिवहन करते दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

टोंक। पीपलू। जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देश पर पीपलू थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से अवैध बजरी से भरे दो बिना नंबरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए हैं। दोनों ही मामलों में पुलिस को देखकर चालक मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने कुल 16 टन अवैध बजरी जब्त कर एमएमडीआर एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव व वृत्ताधिकारी रामअवतार के सुपरविजन में पीपलू थानाधिकारी रवीश सामरिया के नेतृत्व में दो विशेष टीमों का गठन किया गया था।

पहली टीम ने डिग्गी सोहेला रोड पर मांसी नदी के पास नाकेबंदी के दौरान करीब 8 टन बजरी से भरे एक महिन्द्रा ट्रैक्टर-ट्रॉली को रुकवाया। पुलिस को देख चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर आरोपी स्वामी व चालक के खिलाफ प्रकरण संख्या 96/2026 दर्ज किया है।इसी तरह, दूसरी टीम ने गहलोद नाथडी रोड पर ढूंढिया रपटा के पास कार्रवाई की।

वहां से भी करीब 8 टन अवैध बजरी से भरा दूसरा बिना नंबरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किया गया।

इस मामले में भी चालक फरार होने में कामयाब रहा, जिसके खिलाफ प्रकरण संख्या 97/2026 दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

थानाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।

ब्लैकलिस्ट सूची में नाम आने से छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं, स्कूल पूरी तरह संचालित है : गीतिका सेठी

पंचकूला (अमरपाल नूरपुरी)
हरियाणा के 1107 निजी स्कूलों को लेकर जारी हुई ब्लैकलिस्ट संबंधी सूची के बाद अभिभावकों और विद्यार्थियों के मन में कई तरह की शंकाएं पैदा हो गई हैं। इसी विषय पर पंचकूला स्थित पूर्व निदेशक ब्रिटिश स्कूल गितिका सेठी टिंकरबेल स्कूल के निदेशक ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्थिति स्पष्ट की।

उन्होंने कहा कि अभिभावकों और विद्यार्थियों को किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। स्कूल पहले की तरह नियमित रूप से संचालित हो रहा है और विद्यार्थियों की पढ़ाई तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियां बिना किसी बाधा के जारी हैं।

गीतिका सेठी ने बताया कि ब्लैकलिस्ट संबंधी विषय एक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि किसी प्रकार की औपचारिकता या दस्तावेजों से जुड़ा कोई मामला है, तो उसे नियमानुसार संबंधित विभाग के समक्ष रखा जा रहा है। इसका छात्रों की पढ़ाई या उनके भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे किसी भी भ्रामक सूचना या सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें। किसी भी जानकारी के लिए सीधे स्कूल प्रशासन से संपर्क करें, ताकि सही और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हो सके।

स्कूल प्रबंधन ने दोहराया कि विद्यार्थियों के हित सर्वोपरि हैं और उनकी शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रहेगी।

दावत-ए-इस्लामी हिंद के जीएनआरएफ ने चलाया वृक्षारोपण अभियान

डॉ उदय शंकर भगत वाराणसी। दावत-ए-इस्लामी हिंद के फलाही शोबा जीएनआरएफ द्वारा बुनकर पार्क बुनकर कॉलोनी नाटी इमली में वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेतगंज थानाप्रभारी इंस्पेक्टर विजय शुक्ला ने पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया इस अवसर पर जीएनआरएफ के पदाधिकारियों ने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर छायादार एवं फलदार पौधे लगाए जाएंगे तथा उनकी देखभाल भी की जाएगी उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की कार्यक्रम में दानिश भाई हाजी असलम डॉ. साजिद डॉ. मोबाशिर सरफराज मुफ्ती इमरान शाहिद भाई सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने गांवों में सफाई व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण

जयपुर, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने रविवार को जोधपुर से बिराई गांव जाते समय बावड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गांवों में सार्वजनिक स्थानों, मुख्य मार्गों तथा आबादी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का अवलोकन करते हुए ग्रामीणों से पंचायत स्तर पर की जा रही नियमित सफाई और कचरा संग्रहण व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली।

भवात में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा–

श्री दिलावर ने सर्वप्रथम ग्राम पंचायत भवात के गांव भवात में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने गांव में पंचायत द्वारा प्रतिदिन करवाई जा रही सफाई, घरों एवं सार्वजनिक स्थानों से कचरा एकत्रित करने तथा उसके समुचित निस्तारण के संबंध में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों से पूछा कि पंचायत की ओर से सफाईकर्मी नियमित रूप से गांव में आते हैं अथवा नहीं तथा घरों और गलियों से कचरा संग्रहण की व्यवस्था निर्धारित समय पर संचालित हो रही है या नहीं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए नियमित सफाई के साथ-साथ कचरे का समयबद्ध संग्रहण और सुरक्षित निस्तारण आवश्यक है।

गंगाणी में ग्रामीणों से लिया फीडबैक–

इसके पश्चात पंचायती राज मंत्री ने ग्राम पंचायत गंगाणी के गांव गंगाणी में सफाई व्यवस्था का

औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से पंचायत द्वारा प्रतिदिन सफाई करवाने, गलियों और सार्वजनिक स्थानों से कचरा उठाने तथा गांव में स्वच्छता बनाए रखने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतें सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें तथा सार्वजनिक स्थानों, मुख्य मार्गों और आबादी क्षेत्रों में कचरा एकत्रित नहीं होने दिया जाए। सफाई कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रतिदिन कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया जाए।

सेवकी कलां में भी किया निरीक्षण–

श्री दिलावर ने ग्राम सेवकी कलां में भी सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने गांव में सफाई की स्थिति देखते हुए ग्रामीणों से प्रतिदिन सफाई एवं कचरा संग्रहण व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि गांवों में सफाई व्यवस्था को नियमित, प्रभावी और परिणामपरक बनाया जाए। सफाईकर्मियों की उपस्थिति एवं कार्यों की नियमित निगरानी की जाए तथा गांवों से एकत्रित कचरे का निर्धारित स्थान पर समुचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

स्वच्छता व्यवस्था की नियमित निगरानी करें ग्राम पंचायतें–

पंचायती राज मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में सफाई की स्पष्ट कार्ययोजना बनाकर उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। गांवों की गलियों, सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों के आसपास तथा प्रमुख आवागमन मार्गों पर विशेष रूप से स्वच्छता बनाए रखी जाए।

उन्होंने कहा कि कचरा संग्रहण की व्यवस्था केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि प्रतिदिन निर्धारित समय पर कचरा एकत्रित कर उसका वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से निस्तारण किया जाए। नालियों की नियमित सफाई की जाए तथा पानी और गंदगी का जमाव नहीं होने दिया जाए।

मुख्यमंत्री के 'एक पुलिस, एक संकल्प झ नशा मुक्त हरियाणा' अभियान को जन-जन तक पहुंचाएगी हिसार पुलिस : एसपी सिद्धांत जैन

हिसार, (सुरेश रहेजा,परवीन कुमार, साहिल रहेजा)
हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा शुरू किए गए "एक पुलिस, एक संकल्प झ नशा मुक्त हरियाणा" अभियान को सफल बनाने के लिए हिसार पुलिस पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पुलिस अधीक्षक हिसार श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जनसहयोग से ही हरियाणा को पूर्णतः नशा मुक्त बनाया जा सकता है।

एसपी श्री सिद्धांत जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए संदेश के अनुरूप हिसार पुलिस नशा तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ-साथ युवाओं को नशे से बचाने, नशा पीड़ितों का उपचार कराने तथा समाज में व्यापक जनजागरूकता फैलाने का कार्य लगातार कर रही है। जिले में नशा मुक्ति टीम द्वारा गांव-गांव, स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नशे की समस्या केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। इसलिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति को नशे की लत है तो उसे उपचार के लिए प्रेरित करें और यदि कहीं नशा तस्करी की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को अवगत कराएं। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

एसपी ने कहा कि हिसार पुलिस मुख्यमंत्री के "एक पुलिस, एक संकल्प झ नशा मुक्त हरियाणा" अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। नशा तस्करों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के साथ-साथ नशा पीड़ितों के पुनर्वास और उपचार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

उन्होंने जिले के सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, शिक्षण संस्थानों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं एवं युवा क्लबों से आह्वान किया कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। "एक पुलिस, एक संकल्प" तभी सफल होगा जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति नशे के खिलाफ जागरूक होकर आगे आएगा और मिलकर नशा मुक्त हिसार, नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को साकार करेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अग्रणी राष्ट्र बन रहा भारत

पूरी दुनिया में पहुंची भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपरा

जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य हनुमान कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वामी गोविन्द देव गिरी जी महाराज जैसे संतों के सान्निध्य में होने वाले धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मकता और उच्च संस्कारों का संचार करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आज अमृत काल में है और दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों के रूप में उभर रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने जिस सांस्कृतिक वैभव का सपना देखा था, आज हमारी संस्कृति उसी रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। उन्होंने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार नए भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री ने 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए कहा कि लंबे इंतजार के बाद जब प्रभु राम की प्राण-प्रतिष्ठा हुई, तो पूरी दुनिया उस पल की साक्षी बनी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और विरासत के संरक्षण का कार्य निरन्तर कर रही है। खाटूश्याम जी, गिरराज जी और पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर सहित प्रमुख धार्मिक केंद्रों के विकास के लिए सरकार काम कर रही है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का वैदिक परंपरा के अनुरूप मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का वाचन कर रहे बटुकों के वैदिक मंत्रोच्चार का श्रवण किया। हनुमान कथा के दौरान उपस्थित श्रद्धालु भक्तिभाव में सराबोर नजर आए। इस अवसर पर विधायक बालमुकुंद आचार्य, ठाकुर गोविन्ददेव चतुर्वेद विद्यापीठ के न्यासी संदीप झंवर सहित अन्य पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

हिमाचल के मुख्यमंत्री ने टाई चंडीगढ़ लीडरशिप कॉन्क्लेव में की शिरकत

चंडीगढ़, (अमरपाल नूरपुरी): उत्तर भारत के प्रमुख उद्यमी संगठनों में से एक टाई,चंडीगढ़ ने हयात रीजेंसी, चंडीगढ़ में अपना लीडरशिप क कार्यक्रम में 300 से अधिक उद्यमी, स्टार्टअप फाउंडर्स, निवेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, नीति निमार्ता, शिक्षाविद और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए। लीडरशिप कॉन्क्लेव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

पिछले दो दशकों में टाई चंडीगढ़ ने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चैप्टर ने मेंटरशिप, निवेशकों से जुड़ने के अवसर, इनक्यूबेशन सपोर्ट, ज्ञान साझा करने के कार्यक्रम, नीतिगत सुझाव और नेतृत्व विकास जैसी कई पहल के माध्यम से स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया है। टाई चंडीगढ़ ने नए उद्यमियों को सफल व्यवसायियों, एंजेल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फर्मों, कॉरपोरेट कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ने का भी काम किया है।

मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए टाई चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट पुनीत वर्मा ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है। हिमाचल प्रदेश बेहतर नीतियों, मजबूत डिजिटल ढांचे और पर्यटन, एग्री-टेक, फूड प्रोसेसिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाओं, विनिर्माण, आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों के कारण नवाचार आधारित निवेश का उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में उत्तर भारत में उद्यमिता की संस्कृति विकसित करने में टाई चंडीगढ़ के योगदान की सराहना की।

उन्होंने कहा, "टाई चंडीगढ़ लीडरशिप कॉन्क्लेव में शामिल होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं टाई चंडीगढ़ परिवार को बधाई देता हूं, जिसने नवाचार, उद्यमिता और नेतृत्व के क्षेत्र में इस क्षेत्र का एक प्रभावशाली मंच तैयार किया है।"

मुख्य सचिव ने वीसी के माध्यम से ली समीक्षा बैठक

प्रभुराम चौधरी बिजोवा
जयपुर, मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रत्येक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला की नामवार लिस्ट तैयार करें। साथ ही एएनएम तथा सीएचओ को प्रत्येक हाईरिस्क गर्भवती महिला के साथ नियमित मॉनिटरिंग के लिए अटैच करें। आवश्यकता होने पर रेफरल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रदेशभर के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारियों को सोमवार को सुबह एएनएम की बैठक लेकर लाईनलिस्ट और उसके कारणों की समीक्षा के निर्देश दिए। ताकि समय रहते आवश्यक इंटरवेंशन किया जा सके।

मुख्य सचिव ने रविवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य गतिविधियों की विस्तार से जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सामाजिक कामों पर फालतू खर्च कम करें, कर्ज के चक्कर से बचें" के.वी.के. बठिंडा ने किसानों से अपील की

बठिंडा, : (सुरेश रहेजा,परवीन कुमार, साहिल रहेजा)
पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (पी ए यू) लुधियाना की गाइडलाइंस के तहत कृषि विज्ञान केंद्र (के.वी.के.), बठिंडा ने गांव कोटली साबो (ब्लॉक संगत) में एक दिन का स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गनाइज किया।

कैंप का मुख्य मकसद किसानों को खेती और सामाजिक समस्याओं का हल बताना, साथ ही उनकी मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखना और उन्हें स्ट्रेस-फ्री लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट करना था। इस कैंप में इलाके के करीब 40 किसानों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया।

कैंप के दौरान, किसानों को सामाजिक लेवल पर जागरूक किया गया और उनसे खेती के इनपुट का बैलेंस्ड तरीके से इस्तेमाल करने और कर्ज के जाल से बचने के लिए परिवार या सामाजिक कामों पर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचने की अपील की गई।

इस मौके पर प्रोफेसर (एक्सटेंशन एजुकेशन) डॉ. गुरमीत सिंह ढिल्लों ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर खेती और घर के काम समय पर किए जाएं, तो मेंटल स्ट्रेस से काफी हद तक बचा जा सकता है। उन्होंने किसानों को किसी भी मुश्किल हालात में घबराने की नहीं, बल्कि मानसिक तनाव बढ़ाने वाली वजहों से सावधान रहने की हिम्मत दी। उन्होंने डॉक्टरी सलाह और रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज के साथ सही इलाज की जरूरत पर भी खास जोर दिया।

इस मौके पर, डॉ. तेजबीर सिंह बुट्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर (सॉइल साइंस) ने किसानों को संबोधित करते हुए, उन्हें मिट्टी की सेहत बनाए रखने के लिए बैलेंस्ड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने और मिट्टी की टेस्टिंग के आधार पर फर्टिलाइजर डालने की अहमियत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गैर-जरूरी फर्टिलाइजर और केमिकल के इस्तेमाल से न सिर्फ. खेती का खर्च बढ़ता ह।

नशे के खिलाफ जनसहयोग ही सबसे बड़ी ताकत, प्रत्येक पीड़ित तक उपचार और प्रत्येक तस्कर तक कानून पहुंचेगा : एसपी हिसार

हिसार,(सुरेश रहेजा,परवीन कुमार, साहिल रहेजा)
पुलिस अधीक्षक हिसार श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस के सफल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से हिसार पुलिस की नशा मुक्ति टीम द्वारा लगातार जागरूकता एवं उपचार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव खैरमपुर, गांव सदलपुर की ढाणी छीपा तथा जंभ शक्ति चौक के समीप ढाणी में नशा विरोधी जनजागरूकता अभियान आयोजित किया गया।

अभियान के दौरान नशा मुक्ति टीम ने दोनों गांवों के सरपंचों, गणमान्य नागरिकों, नशा पीड़ितों एवं उनके परिजनों से संवाद कर नशे के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। टीम ने ग्रामीणों को बताया कि नशा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित करता है। इसलिए नशे से पीड़ित व्यक्तियों को उपचार के लिए आगे लाना तथा नशा तस्करों के संबंध में पुलिस को गोपनीय सूचना देना समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

अभियान के दौरान टीम ने नशा पीड़ितों को उपचार के लिए प्रेरित करते हुए 03 नए नशा पीड़ितों की पहचान की। साथ ही 05 नशा पीड़ितों को पहली बार नागरिक अस्पताल हिसार से आयुर्वेदिक दवाइयां उपलब्ध करवाई गईं। इसके अतिरिक्त 06 नशा पीड़ितों के घर जाकर नशा मुक्ति पुलिस टीम द्वारा पहली बार आयुर्वेदिक दवाइयां पहुंचाई गईं। वहीं 03 नशा पीड़ितों को दूसरी बार सरकारी अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र से उपचार एवं दवाइयां दिलवाई गईं।

कुल 14 नशा पीड़ितों को घर-घर जाकर आयुर्वेदिक एवं सरकारी अस्पताल से एलोपैथिक उपचार, आवश्यक ब्लड टेस्ट तथा काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई, ताकि वे नशे की लत से बाहर निकलकर सामान्य जीवन की ओर लौट सकें।

पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन ने कहा कि हिसार पुलिस का उद्देश्य केवल नशा तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि नशे के शिकार युवाओं को उपचार एवं पुनर्वास के माध्यम से मुख्यधारा में वापस लाना भी है। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति नशे का आदी है तो उसे उपचार के लिए प्रेरित करें तथा यदि किसी नशा तस्कर की जानकारी हो तो उसकी सूचना।

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन

बठिंडा, (सुरेश रहेजा,परवीन कुमार, साहिल रहेजा)
नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (नालसा) और पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (पल्सा) की गाइडलाइंस के तहत और श्री करुणेश कुमार, माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बठिंडा और सुश्री बलजिंदर कौर मान, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) सी जे एम-कम-सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, बठिंडा की अच्छी लीडरशिप में, आज पूरे ज्यूडिशियल डिस्ट्रिक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के सेक्शन 138 (चेक बाउंस केस) के तहत मामलों के निपटारे के लिए एक स्पेशल लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

श्री करुणेश कुमार, माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बठिंडा ने बताया कि झगड़ों का आसानी से और असरदार तरीके से हल पक्का करने के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कुल 06 स्पेशल बेंच बनाई गईं। इनमें से 02 बेंच हेडक्वार्टर, बठिंडा में, 02 बेंच सब-डिवीजन तलवंडी साबो में और 02 बेंच सब-डिवीजन फूल में बनाई गईं।

माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज-कम-चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बठिंडा श्री करुणेश कुमार ने आगे बताया कि इस कैपेन को केस करने वालों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिससे पेंडिंग केसों की संख्या में भारी कमी आई।

आज की स्पेशल लोक अदालत के दौरान, कुल 728 पेंडिंग केस आपसी सहमति से सुलझाने के लिए बेंचों के सामने पेश किए गए। इनमें से कुल 72 केस आपसी सहमति से मौके पर ही सुलझा दिए गए। कुल 1,78,07,565/- रुपये (एक करोड़ अठहत्तर लाख सात हजार पांच सौ पैंसठ रुपये) के क्लेम आपसी सहमति से निपटाए गए, जिससे कई परेशान पार्टियों को बड़ी राहत मिली।

भा ज पा महानगर एवं जिला की विधानसभाओं के मंडल अध्यक्षों व महामंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न

डॉ उदय शंकर भगत वाराणसी ' महानगर कार्यालय गुलाब बाग में आगामी 22 जुलाई को होने वाले बूथ सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने और संगठनात्मक तैयारियों को धार देने के लिए महानगर एवं जिला की विधानसभाओं के मंडल अध्यक्षों एवं महामंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक चुनाव की नींव हमारा बूथ कार्यकर्ता होता है बूथ सम्मेलन के माध्यम से हमें संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करना है उन्होंने सभी पदाधिकारियों को पूरी ऊर्जा के साथ तैयारियों में जुटने का आह्वान करते हुए कहा महानगर एवं जिला के विधानसभाओं के अंतर्गत आने वाले सभी बूथों पर कार्यकताओं की सक्रियता और जनसंपर्क अभियान को तेज किया जाए मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में प्रवास कर सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करें ताकि यह आयोजन पूरी तरह सफल हो सके सभी पदाधिकारियों ने बूथ सम्मेलन को सफल बनाने और संगठन के दिशा-निदेर्शों का पूरी निष्ठा से पालन करने का संकल्प लिया बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष रामसकल पटेल राहुलसिंह जगदीश त्रिपाठी मधुकर चित्रांश अभिषेक मिश्रा अशोक जाटव आलोक श्रीवास्तव साधना वेदांती प्रवीण सिंह गौतम जेपी दुबे सुरेंद्र पटेल प्रीति सिंह मनोज सोनकर पीयूष भट्टाचार्य आदि रहे।

राजस्थान के निवेश प्रोत्साहन प्रयासों पर लगी राष्ट्रीय मुहर

जयपुर, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे प्रयासों पर राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुहर लगी है। नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को ह्यअग्रणी राज्यह्ल की श्रेणी में स्थान मिला है। समग्र रैंकिंग में राज्य देशभर में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा। वहीं, बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण में राजस्थान ने दूसरा, निवेश प्रोत्साहन नीतियों में तीसरा तथा संसाधनों के क्षेत्र में पांचवां स्थान प्राप्त किया है। यह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और कारोबार को आसान बनाने की दिशा में किए गए सुधारों का परिणाम है।

राज निवेश पोर्टलः अब 190 सेवाएं उपलब्ध, निस्तारण समय में आ रही कमी

राज्य में उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने, निवेशकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने, औद्योगिक भूमि, आधारभूत सुविधाओं तथा निवेश-अनुकूल वातावरण विकसित करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव अब नीति आयोग की रिपोर्ट में भी दिखाई दिया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में नियामकीय सुगमता के क्षेत्र में राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है।

राज्य सरकार ने निवेशकों को तेज, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज निवेश पोर्टल को लगातार सुदृढ़ किया है। वर्तमान में इस पोर्टल पर 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पोर्टल पर कुल 34,704 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 30 जून तक कुल 30 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 17 हजार से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है। इस अवधि में आवेदनों के निस्तारण की समग्र दर 64 प्रतिशत रही, जबकि सर्वाधिक उपयोग वाली 11 प्रमुख सेवाओं में यह दर 68 प्रतिशत रही। साथ ही, प्रमुख सेवाओं के औसत निस्तारण समय में कमी दर्ज की गई है।

प्रदेश में नए विद्युत कनेक्शन की औसत स्वीकृति अवधि पिछले वित्तीय वर्ष के 20 दिनों से घटकर 10 दिन हो गई है, इसी प्रकार पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति अवधि 22 दिनों से घटकर 16 दिन हो गई है। पिछले ढाई वर्षों में 30 से अधिक नई नीतियां लागू

राज्य सरकार द्वारा पिछले ढाई वर्षों में निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 30 से अधिक नई नीतियां लागू की गई हैं। इनमें एमएसएमई, निर्यात प्रोत्साहन, टेक्सटाइल एवं अपैरल, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस एवं डिफेंस जैसी सेक्टर आधारित नीतियां शामिल हैं। साथ ही, इसमें कई ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं, जिनके लिए राजस्थान में पहली बार नीतियां बनाई गई हैं। इन्हीं व्यापक नीतिगत सुधारों का परिणाम है कि नीति आयोग ने निवेश प्रोत्साहन के लिए बनाई गई सरकारी नीतियों के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को देश में तीसरा स्थान दिया है।

राजस्थान में निवेशकों का विश्वास लगातार हो रहा मजबूत

नीति आयोग के इस सूचकांक की विशेषता यह है कि इसमें केवल सरकारी आंकड़ों के आधार पर ही मूल्यांकन नहीं किया गया है, बल्कि देशभर के निवेशकों से प्राप्त सुझावों और अनुभवों को भी शामिल किया गया है।

सागर ब्लॉक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं की समीक्षा, स्वयं सहायता समूहों के कार्य से प्रभावित हुए अवर सचिव

रमेश राय गंगासागर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अवर सचिव अविनाश भट्टाचार्य ने शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले के सागर ब्लॉक और गंगासागर ग्राम पंचायत क्षेत्र का दौरा कर केंद्र सरकार की विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करना और उनके प्रभाव का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना था।

कोलकाता से पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले विभूग्राम-जी (वीबीजीआरएएम-जी) परियोजना के तहत चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना से जुड़े कर्मचारियों, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की टीम के सदस्यों से बातचीत कर योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारी ली। उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया।

इसके बाद सागर ब्लॉक कार्यालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति का विस्तार से आकलन किया। बैठक में योजनाओं के कार्यान्वयन, लाभार्थियों तक पहुंच और समयबद्ध निष्पादन पर चर्चा की गई।

दौरे के दौरान ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों पर विशेष जोर दिया गया। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया। अवर सचिव ने उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना करते हुए महिलाओं से बातचीत की और इस बात पर चर्चा की कि इन उत्पादों के बेहतर विपणन के माध्यम से उनकी आय और आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ाई जा सकती है।

निरीक्षण के बाद अविनाश भट्टाचार्य ने विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकारी योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

इस अवसर पर राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी अनित नंदी भी उपस्थित थे।

दौरा समाप्त करने के बाद अवर सचिव शाम को कोलकाता लौट गए।

उत्तराखंड की सूनी होती धरती और बढ़ता पलायन

कांतिलाल मांडोत

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि केवल पांच वर्षों के भीतर राज्य में लगभग 63 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर हो गई है। अल्मोड़ा और पौड़ी जैसे जिलों में सबसे अधिक खेत खेती से बाहर हो चुके हैं। जिन सीढ़ीदार खेतों में कभी हरियाली लहलहाती थी, वे अब घास और झाड़ियों से भर गए हैं। गांवों के आसपास फैले खेत चारागाह में बदलते जा रहे हैं। यह दृश्य केवल कृषि संकट का नहीं बल्कि पहाड़ की बदलती सामाजिक तस्वीर का भी संकेत है।

जब खेत बंजर हों रोजगार सीमित हो और गांवों से टूटने लगे जीवन का रिश्ता...

उत्तराखंड को प्रकृति ने अपार सौंदर्य, घने जंगल, स्वच्छ जलस्रोत और उपजाऊ सीढ़ीदार खेतों का वरदान दिया है। कभी यही खेत पहाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते थे। मंडुवा, झंगोरा, गहत, चावल, मक्का और अन्य पारंपरिक फसलें न केवल लोगों की आजीविका का आधार थीं, बल्कि पहाड़ी संस्कृति और जीवनशैली की पहचान भी थीं। आज वही खेत तेजी से बंजर होते जा रहे हैं। गांव खाली हो रहे हैं, खेती से लोगों का भरोसा उठ रहा है और रोजगार की तलाश में युवा पहाड़ छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह केवल कृषि संकट नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन चुका है।

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की सबसे बड़ी चुनौती आजीविका के सीमित साधन हैं। राज्य का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा पर्वतीय है और आधे से अधिक लोग इन्हीं इलाकों में रहते हैं। यहां उद्योगों का विकास सीमित है और सरकारी नौकरियां भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में खेती और पशुपालन ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन क्षेत्रों का योगदान लगातार घटा है। एक समय राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का योगदान लगभग 14 प्रतिशत था, जो अब घटकर लगभग 9 प्रतिशत के आसपास रह गया है। यह गिरावट बताती है कि खेती अब लोगों के लिए लाभ का नहीं बल्कि संघर्ष का माध्यम बनती जा रही है।

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि केवल पांच वर्षों के भीतर राज्य में लगभग 63 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर हो गई है। अल्मोड़ा और पौड़ी जैसे जिलों में सबसे अधिक खेत खेती से बाहर हो चुके हैं। जिन सीढ़ीदार खेतों में कभी हरियाली लहलहाती थी, वे अब घास और झाड़ियों से भर गए हैं। गांवों के आसपास फैले खेत चारागाह में बदलते जा रहे हैं। यह दृश्य केवल कृषि संकट का नहीं बल्कि पहाड़ की बदलती सामाजिक तस्वीर का भी संकेत है।

खेती से लोगों का मोहभंग कई कारणों से हुआ है। सबसे पहला कारण लगातार बढ़ता पलायन है। जब गांव के युवा रोजगार के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं तो खेतों में काम करने वाले हाथ कम पड़ जाते हैं। बुजुर्ग और महिलाएं अकेले पूरी खेती नहीं संभाल पातीं। धीरे-धीरे खेत खाली छोड़ दिए जाते हैं और फिर वे बंजर हो जाते हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड के अनेक गांव आज जनसंख्या घटने और खेती समाप्त होने की दोहरी मार झेल रहे हैं।

दूसरा बड़ा कारण जंगली जानवरों का बढ़ता आतंक है। जंगलों से निकलकर बंदर, लंगूर, जंगली सुअर, नीलगाय और अन्य वन्यजीव खेतों में घुसकर पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। किसान पूरे वर्ष मेहनत करता है लेकिन कटाई से पहले ही फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसान का मनोबल टूटना स्वाभाविक है। कई गांवों में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोग खेती करने का जोखिम ही नहीं उठाना चाहते। खेती में लागत बढ़ती जा रही है लेकिन उत्पादन की कोई गारंटी नहीं बची है।

तीसरी समस्या सिंचाई की कमी है। उत्तराखंड के अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में खेती आज भी वर्षा पर निर्भर है। यदि मानसून समय पर नहीं आए या बारिश कम हो जाए तो पूरी बुआई प्रभावित हो जाती है। आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का अभाव किसानों की परेशानी और बढ़ा देता है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की अनिश्चितता ने भी खेती को पहले से अधिक जोखिम भरा बना दिया है।

चौथा कारण खेती से मिलने वाला सीमित लाभ है। पहाड़ों में छोटे-छोटे खेत, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और परिवहन की ऊंची लागत किसानों की आय को सीमित कर देती है। यदि फसल अच्छी भी हो जाए तो उसे बाजार तक पहुंचाना महंगा पड़ता है। किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता और उसकी मेहनत का लाभ बिचौलियों तक सीमित रह जाता है। यही वजह है कि अनेक परिवार अब केवल अपने घरेलू उपयोग के लिए खेती कर रहे हैं, जबकि नकदी आय के लिए परिवार का कोई सदस्य शहरों में मजदूरी या नौकरी करने को मजबूर है।

महिलाओं पर इस संकट का सबसे अधिक प्रभाव दिखाई देता है। पहाड़ों में पुरुषों के पलायन के बाद खेती, पशुपालन, घर और परिवार की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। बढ़ती उम्र, सीमित संसाधन और जंगली जानवरों के खतरे के बीच खेती करना उनके लिए लगातार कठिन होता जा रहा है। अनेक महिलाएं मानती हैं कि अब खेती केवल परंपरा निभाने तक सीमित रह गई है, क्योंकि इससे परिवार का खर्च चलाना संभव नहीं रह गया है।

खेती में गिरावट का असर केवल किसानों तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव पूरे ग्रामीण समाज पर पड़ रहा है। गांवों में स्कूल बंद होने की स्थिति बन रही है, स्थानीय बाजारों की गतिविधियां कम हो रही हैं और पारंपरिक संस्कृति भी कमजोर पड़ रही है। जब गांव खाली होते हैं तो वहां की सामाजिक संरचना भी टूटने लगती है। त्योहार, मेलों और सामुदायिक जीवन की रौनक धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है। पलायन केवल लोगों का स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि पूरे सामाजिक ताने-बाने में बदलाव लेकर आता है।

फसलों के आंकड़े भी इस संकट की गंभीरता को स्पष्ट करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में चावल, मंडुवा, सावा और मक्का जैसी प्रमुख फसलों के रकबे में उल्लेखनीय कमी आई है। विशेष रूप से मंडुवा और सावा जैसी पारंपरिक मोटे अनाज की खेती में लगभग एक चौथाई से अधिक गिरावट दर्ज की गई है। जबकि आज पूरी दुनिया मोटे अनाज को पोषण और जलवायु अनुकूल खेती के रूप में बढ़ावा दे रही है, उत्तराखंड में इनकी खेती सिमटती जा रही है। यह स्थिति चिंता का विषय है।

यदि इस समस्या का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के अनेक गांव पूरी तरह खाली हो सकते हैं। इसलिए केवल खेती को बचाने की नहीं बल्कि पूरे पहाड़ी जीवन को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। सरकार को सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना होगा, जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के प्रभावी उपाय करने होंगे, पर्वतीय कृषि के लिए विशेष सहायता और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा। स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रसंस्करण और बेहतर विपणन व्यवस्था विकसित करने से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, औषधीय पौधों की खेती और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित करने होंगे ताकि युवाओं को गांव छोड़ने की मजबूरी न रहे।

उत्तराखंड की पहचान केवल उसके पहाड़ों और पर्यटन से नहीं बल्कि उसके जीवंत गांवों और हरे-भरे खेतों से भी है। यदि खेत सूने हो जाएंगे और गांव खाली हो जाएंगे तो पहाड़ की आत्मा भी कमजोर पड़ जाएगी। आज आवश्यकता केवल आंकड़ों पर चिंता व्यक्त करने की नहीं बल्कि ऐसी नीतियां बनाने की है जो खेती को लाभकारी बनाएं, ग्रामीण जीवन को सम्मानजनक बनाएं और युवाओं को अपने गांव में ही भविष्य दिखाई दे। तभी उत्तराखंड के बंजर होते खेत फिर से हरियाली से भर सकेंगे और पलायन की जगह विकास की नई कहानी लिखी जा सकेगी।

(वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार-स्तम्भकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

हाइड्रोजन ट्रेन

देश की पहली हाइड्रोजन ऊर्जा से चलने वाली रेल की शुरूआत ने भारत में साफ-सुथरे और कम प्रदूषण वाले ट्रांसपोर्ट की ओर बदलाव की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को हरियाणा में हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट- ह्यमेक इन इंडियाह्न की सफलता के प्रतीक के तौर पर भी प्रस्तुत किया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो यह पूरी दुनिया को संदेश देने का प्रयास ही है कि आज भारत पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को प्राथमिकता देने के लिये प्रतिबद्ध है। यानी हम भी इस क्षेत्र के ग्लोबल लीडर्स में शामिल होने के आकांक्षी हैं। निश्चित रूप से हाइड्रोडन फ्यूल सेल से चलने वाली यह 10-कोच वाली ट्रेन, जिसमें सिर्फ पानी की भाप ही निकलती है, डीजल इंजनों का पर्यावरण अनुकूल विकल्प भी है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के जींद में स्वदेशी टेक्नोलॉजी और स्थानीय स्तर पर विकसित हाइड्रोजन इकोसिस्टम के साथ, यह प्रोजेक्ट एडवांस्ड इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दशार्ता है। वहीं दूसरी ओर यह प्रोजेक्ट देश के ह्यनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशनह्न को भी संबल देने वाला है। जिसका उद्देश्य आयातित जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करना तो है ही, साथ ही दीर्घकाल में देश के नेट-जीरो के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग बढ़ाना भी है। सही मायने में देश में ग्रीन हाइड्रोजन का रणनीतिक महत्व जलवायु संबंधी चिंताओं से कहीं आगे बढ़कर है। हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते अमेरिका व ईरान के संघर्ष से उपजे विषम हालातों ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत को एकबार फिर से रेखांकित किया है। ऐसे में आयातित कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और औद्योगिक फीडस्टॉक पर भारत की भारी निर्भरता के कारण ऊर्जा सुरक्षा आज देश की राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है। विशेष रूप से वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौर में। आज के वैश्विक अशांति के समय में ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय संप्रभुता की संरक्षा के लिए अपरिहार्य शर्त बन गई है।

चिंतन-मनन

सुख की उपेक्षा क्यों?

मेरे पास लोग आते हैं। जब वे अपने दुख की कथा रोने लगते हैं, तो बड़े प्रसन्न मालूम होते हैं। उनकी आंखों में चमक मालूम होती है। जैसे कोई बड़ा गीत गा रहे हों! अपने घाव खोलते हैं, लेकिन लगता है जैसे कमल के फूल ले आए हैं। सुख की तो कोई बात ही नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है; हम सुख पर पर ध्यान नहीं देते हैं। हम दुःख-दुख चुन लेते हैं; हम सुख की उपेक्षा कर देते हैं। फिर जिसकी उपेक्षा कर देते हैं, स्वभावतः धीरे-धीरे वह दूर चला जाता है और जिसमें हम रस लेते हैं वह पास होता चला जाता है।

संतों की बात तुम्हें तभी जमेगी, रुचेगी, भली लगेगी, प्रीतिकर मालूम होगी-जब तुम दुख को पकड़ना छोड़ दोगे; जब तुम जागोगे और सुख की सचेष्ट खोज शुरू करोगे। तुम्हारे भीतर अगर अभी भी दुख को पकड़ने का आयोजन चल रहा है, तो संतों के वचन तुम्हारे कानों में गूजेंगे और खो जाएंगे। तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि संतों के वचनों में बड़ा सुख भरा है। तुम सुखोन्मुख हो जाओ, तुम आनंद की खोज में लग जाओ; तो ये एक-एक शब्द ऐसे जाएंगे तुम्हारे भीतर जैसे तीर चले जाएं। और ये एक-एक शब्द तुम्हारे भीतर ऐसे-ऐसे हजार-हजार फूल खिला देंगे, जैसे कभी न खिले थे। तुम्हारे भीतर बड़ी रोशनी होगी।

ये छोटे-छोटे शब्द हैं। मगर ये बड़े सार्थक शब्द हैं। सुनो- ह्यबोलू हरिनाम तू छोड़ि दे काम सब, सहज में मुक्ति होई जाय तेरी।काम यानी कामना। काम यानी वासना। काम यानी इच्छा, तृष्णा। यह मिले वह मिले-कुछ मिले! जब तक हम मिलने की दौड़ में होते हैं, हम भिखमंगे होते हैं। और जब तक हम भिखमंगे होते हैं, तब तक परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा भिखमंगों को मिलता ही नहीं। परमात्मा सम्राटों को मिलता है। परमात्मा उनको मिलता है जो अपने मालिक है। परमात्मा उनको मिलता है जो कुछ मांगते ही नहीं।

असल में वे ही परमात्मा को मांगने में कुछ सफल हो पाते हैं, जो और कुछ नहीं मांगते। जिन्होंने कुछ और मांगा, वे परमात्मा को कैसे मांगेंगे। वह जबान फिर परमात्मा को मांगने के योग्य न रह गई। वह जबान अपवित्र हो गई। जिस जबान से बेटा मांगा, बेटी मांगी, धन मांगा, पद मांगा, प्रतिष्ठा मांगी-उसी जबान से परमात्मा को मांगोगे? इस जहर भरे पात्र में अमृत रखोगे? यह जबान जब तक मांगती है तब तक संसार है। जिस दिन यह जबान मांगती नहीं, उस दिन परमात्मा की यात्रा शुरू हुई। उस दिन बिन मांगे मिलता है। ऐसे तो मांगे-मांगे भी नहीं मिलता।

सोनम वांगचुक सरकार की निगरानी में, भूत बनकर लौटने की चेतावनी

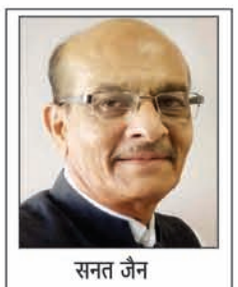

सनत जैन

शिक्षामित्र और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सरकार ने शनिवार की सुबह जंतर मंतर के धरना स्थल से सरकारी निगरानी में ले लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है, कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद चलो मार्च का आह्वान किया था। सोनम वांगचुक ने यह भी कहा था, कि यदि लोग उनका साथ नहीं देंगे तो वह मरने के बाद भूत बनकर जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है उसको लड़ने के लिए वापस आएंगे। इसके बाद से दिल्ली के जंतर मंतर में सरगर्मी बढ़ी। 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार ने गंभीरता को समझते हुए जंतर मंतर से आंदोलन खत्म कराने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को रातों-रात बदल दिया गया है। शिक्षा मंत्री के स्तीफे और पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करने के लिए सभी विपक्षी दलों और फिल्मी जगत की हस्तियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर जिस तरह का समर्थन दिया उससे सरकार की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। मानसून सत्र के दौरान इस तरह के आंदोलन जिसमें आंदोलनकारी संसद में प्रदर्शन करने की मांग पर अड़ गए हैं, विपक्ष भी इस मुद्दे पर एक साथ आ गया है, जिसके कारण सरकार की चिंता बहुत बढ़ गई है। सरकार ने जिस तरह से सोनम वांगचुक को धरना स्थल से हटाया है, उसकी आंदोलनकारियों के बीच में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल देहरादून में छात्रों के साथ संवाद किया। यह कार्यक्रम भी पूरी तरह से सफल रहा। भारी बारिश के बीच लाखों की संख्या में छात्र वहां पहुंचे। उन्होंने अपने दुख- दर्द को सुनाया। कोटा में भी राहुल गांधी के छात्र संवाद को काफी सफल माना गया था। जेन-जी के बीच में जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक है। यह भी कहा जा रहा है, राहुल गांधी से इस मुद्दे को छीनने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन जंतर मंतर में शुरू कराया गया था उसको वह सफलता नहीं मिली जिस सफलता की आशा सरकार कर रही थी। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सरकार के बजाय जिस तरह से विपक्ष को निशाने पर लिया था उसके कारण कॉकरोच पार्टी का यह आंदोलन फ्लॉप होने की दिशा में बढ़ रहा था। इसी बीच कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों ने सोनम वांगचुक को समर्थन देकर एक ऐसी चाल चली जिससे कॉकरोच पार्टी निशाने पर आ गई। अब सरकार ने जब सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को आधार बनाकर अपनी निगरानी में जबरिया ले लिया है, इसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देश भर में हो सकती है। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है, जिसने सरकार की परेशानी को और बढ़ा दिया है। शनिवार को जंतर मंतर में एक बार फिर भीड़ बढ़ने लगी। 20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी में आंदोलनकारी फिर एकजुट होने लगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और पेपर लीक मामले में जिस तरह से युवा एकजुट हो रहे हैं, कई राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं। सरकार ने अभी तक आंदोलनकारियो से कोई बात नहीं की है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर भी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। ऐसी स्थिति में जेन-जी युवा उद्वेलित होकर आक्रामक हो रहे हैं। सरकार को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है।

मानसून सत्र में सरकार परिसीमन बिल को हर हालत में पास करना चाहती है। पिछले दो महीने से संसद में दो तिहाई बहुमत सरकार के पास हो इसके लिए बड़े पैमाने पर कई राज्यों के सांसदों को उनकी पार्टी से तोड़कर एनडीए के पक्ष में लाया गया है। लेकिन इसमें दल-बदल कानून भी बड़ी बाधा बन रहा है। इसी बीच ईरान- अमेरिका युद्ध के कारण कच्चे तेल, एलपीजी गैस एवं खाद इत्यादि की चुनौतियां सरकार के लिए बढ़ रही हैं। ई-20 पेट्रोल को लेकर भी लोगों में नाराजी देखने को मिल रही है। राम मंदिर के दान और चढ़ावा चोरी को लेकर भी सरकार के ऊपर हमले बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार समझ नहीं पा रही है कि एक साथ इतनी सारी समस्याओं और हमलो का मुकाबला वह किस तरीके से करे। सोनम वांगचुक ने यह कहकर युवाओं को उद्वलित कर दिया है कि वह 20 तारीख तक जिंदा रहेंगे, यदि मर भी गए तो वह भूत बनकर आंदोलनकारियों के साथ होंगे। राजधानी दिल्ली में मानसून सत्र के दौरान सरकार को जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने अपने सभी दिग्गजों को इस समस्या से निपटने के लिए जिम्मेदारी दी है। आगे किस तरह के हालात होंगे यह कहना मुश्किल है।

यक्ष प्रश्नः क्या विकसित भारत 2047 का लक्ष्य 2075 में हासिल होगा?

कमलेश पांडेय

यदि आप विकसित भारत 2047 का स्वप्न देख रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क दिया है कि यदि भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि दर, उत्पादकता और रोजगार सृजन की गति में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ, तो भारत को 'विकसित देश' बनने में 2047 के बजाय 2075 तक का समय लग सकता है। बता दें कि यह कोई आधिकारिक सरकारी अनुमान नहीं है, बल्कि कतिपय अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए एक आर्थिक विश्लेषण पर आधारित दृष्टिकोण मात्र है, जो सत्य के निकट है या परे, यह भविष्य के गर्भ में है। हाँ, इतना जरूर है कि इससे विपक्ष को सत्तापक्ष की खिल्ली उड़ाने का एक मौका जरूर मिल गया है।

दरअसल, इस संदर्भ में चर्चित अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने भी कहा कि यदि वर्तमान गति ऐसी ही बनी रही, तो विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक हासिल करना कठिन हो सकता है। मसलन, Surjit Bhalla का आशय यह है कि केवल उच्च आर्थिक वृद्धि दर पर्याप्त नहीं है। यदि वर्तमान गति, निवेश, उत्पादकता और रोजगार सृजन की चुनौतियाँ बनी रहीं, तो भारत को विकसित देश बनने में 2047 के बजाय 2075 तक का समय लग सकता है।

इस प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने और उनके जैसे अन्य कई अर्थशास्त्रियों द्वारा उठाई जाने वाली प्रमुख चिंताएँ इस प्रकार हैं:- पहली, विकास दर में कमीः विकसित भारत के लक्ष्य के लिए लंबे समय तक 8-9% या उससे अधिक वास्तविक GDP वृद्धि की आवश्यकता मानी जाती है, जबकि हाल के वर्षों में वृद्धि इससे कम रहने का अनुमान है।

दूसरी, प्रति व्यक्ति आयः विकसित देश बनने का आधार केवल कुल GDP नहीं, बल्कि प्रति व्यक्ति आय भी है। यदि जनसंख्या के अनुपात में आय पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ती, तो लक्ष्य पीछे खिसक सकता है। तीसरी, रोजगार की चुनौतीः आर्थिक वृद्धि के अनुरूप पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं बनने से आय और उपभोग दोनों प्रभावित होते हैं।

चौथी, विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग): GDP और रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ पाई है। पांचवीं, मानव पूंजीः शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और श्रम उत्पादकता में अभी भी उल्लेखनीय सुधार की आवश्यकता है। छठी, वैश्विक अनिश्चितताएँः भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार बाधाएँ, ऊर्जा कीमतें और वैश्विक आर्थिक मंदी जैसे कारक भी विकास की गति को प्रभावित कर सकते हैं।

हालाँकि, यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि यह एक आर्थिक आकलन है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं। यदि भारत अगले दो दशकों में तेज और निरंतर आर्थिक वृद्धि, व्यापक रोजगार सृजन, विनिर्माण विस्तार, बुनियादी ढाँचे में निवेश, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार और प्रशासनिक सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करता है, तो 2047 का लक्ष्य अधिक यथार्थवादी हो सकता है।

इसलिए सुरजीत भल्ला का तर्क मूलतः यह है कि यदि वर्तमान गति और संरचनात्मक चुनौतियाँ नहीं बदलीं, तो विकसित भारत का लक्ष्य 2047 से काफी आगे खिसक सकता है। इसके पीछे प्रमुख कारण बताए जाते हैं जो इस प्रकार हैंः पहला, विकास दर की चुनौतीः विकसित देशों की श्रेणी में पहुँचने के लिए भारत को लंबे समय तक लगभग 7-8% या उससे अधिक वास्तविक जीडीपी (GDP) वृद्धि बनाए रखनी होगी। यदि वृद्धि 6% के आसपास रहती है, तो लक्ष्य पीछे खिसक सकता है।

दूसरा, प्रति व्यक्ति आय कम होनाः भारत की कुल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बड़ी आबादी के कारण प्रति व्यक्ति आय अभी विकसित देशों से काफी कम है। तीसरा, रोजगार और उत्पादकताः उच्च आर्थिक वृद्धि के साथ गुणवत्तापूर्ण रोजगार और श्रम उत्पादकता में तेज सुधार आवश्यक है। चौथा, विनिर्माण क्षेत्र की धीमी प्रगतिः यदि मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात अपेक्षित गति से नहीं बढ़ते, तो आय वृद्धि सीमित रह सकती है।

पांचवां, शिक्षा और स्वास्थ्यः मानव पूंजी में निवेश पर्याप्त न होने पर दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है। छठा, बुनियादी ढाँचा और संस्थागत सुधारः न्यायिक दक्षता, भूमि, श्रम और प्रशासनिक सुधारों की गति भी निर्णायक मानी जाती है।

वहीं, दूसरी ओर, 2047 के लक्ष्य के समर्थन में भी मजबूत तर्क हैं क्योंकि भारत में सत्ता प्रतिष्ठान के रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड को तोड़ती जा रही भाजपा नीत राजग की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए विकसित भारत 2047 एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। चूंकि भारत की आजादी प्राप्ति का सौवाँ वर्ष है, इसलिए सरकार इसे ज्यादा तवज्जो दे रही है, जबकि वैश्विक षड्यंत्रकारी देश अमेरिका/चीन और उनके पिछलग्गू कट्टर मुस्लिम देश भारत की तरक्की से जल-भुन रहे हैं!

नामचीन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार ऊँची आर्थिक वृद्धि बनाए रखे, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा और विनिर्माण में तेजी से आगे बढ़े, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर जोर दे, तथा राज्यों में सुधारों की गति तेज हो, तो विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य अपेक्षाकृत जल्दी यानी कि 2047 तक या उससे कुछ साल पहले भी हासिल किया जा सकता है।

इसलिए 2047 और 2075 को निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि अलग-अलग आर्थिक परिदृश्यों (शीéल्लंश्९ङ्क्षर) के रूप में देखना चाहिए। अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दो दशकों में भारत सुधारों, निवेश, उत्पादकता, मानव संसाधन विकास की गति और सुशासन व पारदर्शिता कितनी बढ़ा पाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह बढ़कर 675.15 अरब डॉलर पहुंचा

मुंबई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने के मुतो बिक 10 जुलाई को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 96.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 675.15 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यह लगातार दूसरा सप्ताह है जब भारत के भंडार में वृद्धि दर्ज की गई है, जो मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे पिछले सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार में 7.26 अरब डॉलर की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। उल्लेखनीय है कि 27 फरवरी को पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने से पहले यह रिकॉर्ड 728.49 अरब डॉलर पर था। हालांकि, संघर्ष के कारण रुपये पर दबाव बढ़ने और आरबीआई के डॉलर बेचकर बाजार में हस्तक्षेप करने से भंडार में कई सप्ताह तक गिरावट आई थी। अब लगातार दूसरे सप्ताह की वृद्धि मौजूदा दबावों से कुछ राहत का संकेत दे रही है। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 93 करोड़ डॉलर बढ़कर 546.51 अरब डॉलर हो गईं। इसी अवधि में देश के स्वर्ण भंडार का मूल्य 2.4 करोड़ डॉलर बढ़कर 105.22 अरब डॉलर पर पहुंच गया। विशेष आहरण अधिकार 30 लाख डॉलर बढ़कर 18.63 अरब डॉलर तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास भारत का आरक्षित कोष भी 70 लाख डॉलर बढ़कर 4.79 अरब डॉलर दर्ज किया गया है।

इस हफ्ते सोना दो हजार और चांदी में चार हजार रुपए की गिरावट रही

24 कैरेट सोना 1.41 लाख, चांदी 2.15 लाख प्रति किलो के करीब

नई दिल्ली।

इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। भू-राजनीतिक तनाव के बीच 24 कैरेट सोना 2,200 रुपए से अधिक और चांदी 4,900 रुपए से ज्यादा सस्ती हुई है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम 2,209 रुपए कम होकर 1,41,159 प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो पहले 1,43,368 रुपए था। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,29,302 रुपए और 18 कैरेट सोना 1,05,869 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इस हफ्ते सोने का न्यूनतम दाम 17 जुलाई की शाम को 1,41,159 रुपए देखा गया, जबकि उच्चतम दाम 13 जुलाई को सुबह 1,42,289 रुपए रहा। सोने के साथ चांदी में भी 4,917 रुपए की तेज गिरावट दर्ज की गई। चांदी का दाम 2,20,390 रुपए प्रति किलो से गिरकर 2,15,474 रुपए प्रति किलो हो गया। चांदी का उच्चतम दाम 15 जुलाई को सुबह 2,20,391 रुपए और न्यूनतम दाम 17 जुलाई को शाम को 2,15,474 रुपए प्रति किलो रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस और चांदी 57 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक, सोने और चांदी में गिरावट की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है। एक-दूसरे पर लगातार हमलों के चलते वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव आया है।

आरबीआई ने छह कंपनियों पर लगाया लाखों का जुर्माना

नई दिल्ली।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय मानदंडों का पालन न करने के कारण छह वित्तीय और गैर-वित्तीय कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों में प्रमुख रूप से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) मुथूट फाइनेंस और अवेल फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। यह कार्रवाई केंद्रीय बैंक द्वारा जारी अधिसूचना के बाद की गई है, जिसमें नियमों के उल्लंघन की बात कही गई है। आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, मुथूट फाइनेंस पर 5.80 लाख रुपए, अवेल फाइनेंशियल सर्विसेज पर सर्वाधिक 6.20 लाख रुपए, सत्य माइक्रोकैपिटल और पैन एमामी कॉस्मेड पर 3.10-3.10 लाख रुपए, तथा धनी लोन्स एंड सर्विसेज और मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस पर 2.70-2.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि मुथूट फाइनेंस पर यह जुर्माना खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा करने की व्यवस्था लागू करने में विफलता और संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान तथा सूचना के लिए मजबूत सॉफ्टवेयर का उपयोग न करने के कारण लगाया गया है।

भू-राजनीतिक तनाव से बेअसर रहा भारतीय शेयर बाजार

हफ्ते की शुरुआत कमजोर, पर अंत में जोरदार उछाल!

मुंबई ।

बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण सप्ताह की शुरुआत भले ही कमजोर रही हो, लेकिन निवेशकों के दृढ़ विश्वास और कुछ सकारात्मक घरेलू संकेतों ने बाजार को अंततः नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित शक्ति को दर्शाता है। सप्ताह की शुरुआत सोमवार को निराशाजनक रही, जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण सेंसेक्स 650 से अधिक अंक लुढ़का और निफ्टी 24,000 के महत्वपूर्ण स्तर का परीक्षण करता दिखा। हालांकि, आईटी और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के शेयरों में मजबूती से बाजार ने दिन के अंत तक लगभग सपाट स्तर पर वापसी कर ली।

मंगलवार को फिर से भू-राजनीतिक चिंताओं, विदेशी कोषों की निकासी और वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख ने सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को लाल निशान पर बंद होने को मजबूर किया। बुधवार को अमेरिकी खुदरा मुद्रास्फीति की धीमी रफ्तार के अनुमान ने एशियाई बाजारों में खरीदारी का माहौल बनाया, जिससे भारतीय बाजार भी हरे निशान पर खुले और मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। गुरुवार को पश्चिम एशिया में गहराते संघर्ष के बावजूद भारतीय बाजार ने कमजोर वैश्विक संकेतों को दरकिनार करते हुए मजबूती दिखाई।

हालांकि, एक्सपायरी के दिन और ईरान-अमेरिका युद्ध की अनिश्चितताओं के कारण बाजार सपाट बंद हुए, लेकिन यह भारतीय बाजार की अंतर्निहित स्थिरता का प्रमाण था। सप्ताह का अंत धमाकेदार रहा। शुक्रवार को आईटी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी और टेक महिंद्रा के मजबूत तिमाही नतीजों ने बाजार को नई ऊर्जा दी। जब अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे वैश्विक बाजार भारी गिरावट का सामना कर रहे थे, तब भारतीय निवेशकों ने घरेलू बाजार में चौतरफा खरीदारी की। इसके परिणामस्वरूप, सेंसेक्स 964.58 अंक की जोरदार तेजी के साथ 78,151.45 पर और निफ्टी 272.75 अंक चढ़कर 24,345.50 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।

रिकॉर्ड ऊंचाई पर शक्कर, थोक भाव 5000 के पार

भोपाल ।

मीठे का कारोबार अब कड़वा होता जा रहा है, क्योंकि शक्कर के थोक दाम पहली बार 4800-4900 रुपए प्रति क्विंटल पार कर 5000 रुपए तक पहुंचने की आशंका है। खुदरा में यह 5100-5200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। यह तेजी मानसून की अनिश्चितता और बढ़ती मांग का सीधा परिणाम है। बीते एक पखवाड़े में शक्कर 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल महंगी हुई है। भोपाल शक्कर व्यापारी एसोसिएशन के अनुसार पर्याप्त मांग और मानसून की बेरुखी ने कारोबार को तेज किया है। मजबूत मांग और कमजोर आपूर्ति भी बाजार को सपोर्ट कर रही है। ब्रोकरों तथा व्यापारियों का कहना है कि अलनीनो प्रभाव और ब्राजील, थाईलैंड जैसे प्रमुख उत्पादक देशों में भी दाम बढ़ने से इसका असर भारतीय बाजारों पर स्पष्ट दिख रहा है।

बारिश के दिनों में बाइक या स्कूटर को बेहतर स्थिति में रखने बरते सावधानी

नई दिल्ली ।

दो पहिया वाहनों में बरसात के मौसम में सड़कों पर जलभराव और अधिक नमी ब्रेक की क्षमता कम करने, चेन में जंग लगने, बैटरी की समस्या और इंजन में खराबी जैसी दिक्कतें आ सकती है। पूरे मानसून के दौरान अपनी बाइक या स्कूटर को बेहतर स्थिति में रखने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले, टायरों की स्थिति की नियमित जांच करें, घिसे हुए टायरों को तुरंत बदल देना चाहिए और टायरों में निर्धारित मात्रा में हवा बनाए रखना सुरक्षित सफर के लिए जरूरी है, क्योंकि बरसात में सड़कें अधिक फिसलन भरी होती हैं। ब्रेक की कार्यक्षमता पर भी विशेष ध्यान दें, यदि ब्रेक लगाने पर किसी प्रकार की आवाज सुनाई दे या ब्रेक सामान्य से कमजोर महसूस हों तो तुरंत उनकी जांच करानी चाहिए। बाइक की चेन को जंग से बचाने के लिए उसकी नियमित सफाई और चिकनाई करना लाभदायक रहता है। अपने वाहन को लंबे समय तक बारिश में खुले स्थान पर न छोड़ें, और यदि संभव न हो तो अच्छे गुणवत्ता वाले जलरोधी आवरण का उपयोग करें। नमी और धूल के कारण वायु शोधक जल्दी गंदा हो सकता है, इसलिए नियमित अंतराल पर इसकी सफाई कराएं। बैटरी के जोड़ और विद्युत प्रणाली की जांच करते रहें, और जलभराव वाली सड़कों पर बाइक या स्कूटर चलाने से बचें, क्योंकि अधिक पानी में इंजन में पानी जाने का खतरा रहता है। यदि वाहन पानी में बंद हो जाए तो बार-बार चालू करने का प्रयास न करें। बारिश के बाद कीचड़ और गंदे पानी को हटाने के लिए वाहन को साफ पानी से धोकर अच्छी तरह सुखाएं। सफर के दौरान वर्षा से बचाव का वस्त्र, एंटी-फॉग हेलमेट शीशा और पंचर सुधारने का सामान हमेशा साथ रखें। सुरक्षित ड्राइविंग के लिए नियंत्रित गति बनाए रखें, आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाएं और अचानक ब्रेक लगाने से बचें।

डीमैट म्यूचुअल फंड यूनिट्स पर भी एसडब्ल्यू और एसटीपी संभव, सेबी ने दी मंजूरी

निवेशकों को मिलेगी बड़ी सहूलियत, दो चरणों में 2027 तक पूरी तरह लागू होगी सुविधा

- मुंबई ।

बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब डीमैट खातों में रखी म्युचुअल फंड यूनिट्स पर भी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान (एसटीपी) जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह कदम उन लाखों निवेशकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो अपनी म्युचुअल फंड होल्डिंग को डीमैट फॉर्म में रखते हैं और अब तक इन स्वचालित विकल्पों का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। सेबी ने बताया कि यह नई सुविधा दो चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में, 31 जनवरी, 2027 तक यूनिट-आधारित एसडब्ल्यूपी और एसटीपी के लिए पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी, जहाँ निवेशक निश्चित संख्या में यूनिटों को रिडीम या ट्रांसफर कर सकेंगे। दूसरा चरण 30 अप्रैल, 2027 तक लागू होगा, जिसमें यह सुविधा रकम-आधारित एसडब्ल्यूपी और एसटीपी तक बढ़ाई जाएगी, जिससे निवेशक नियमित अंतराल पर तय राशि निकाल या ट्रांसफर कर पाएंगे। नियामक ने डिपॉजिटरीज को 31 अक्टूबर तक आवश्यक परिचालन व्यवस्था स्थापित करने और सिस्टम में बदलाव करने का निर्देश दिया है। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब ऑनलाइन म्युचुअल फंड वितरक, जैसे ग्रो, निवेशकों को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से डीमैट होल्डिंग की ओर तेजी से प्रेरित कर रहे हैं।

एसडब्ल्यूपी निवेशकों को नियमित आय प्राप्त करने में मदद करता है, जबकि एसटीपी एक स्कीम से दूसरी में व्यवस्थित निवेश ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। इस कदम से डीमैट होल्डिंग वाले निवेशकों को भी वही लचीलापन और सुविधा मिल सकेगी जो अब तक केवल एसओए धारकों को मिलती थी।

फीफा फाइनल से अर्थव्यवस्था को बूस्ट, विज्ञापन दरों में दस गुना उछाल

रेस्तरां, पब, मल्टीप्लेक्स और फूड डिलिवरी कंपनियों के लिए में कारोबार का सुनहरा अवसर

मुंबई ।

पिछले लगभग 39 दिनों से दुनिया भर के खेल प्रेमियों पर छाया फीफा विश्व कप फुटबॉल का खुमार अब अपने चरम पर पहुंच गया है। रविवार देर रात अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच होने वाला फाइनल मुकाबला केवल मैदान पर रोमांच ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि मैदान से बाहर भी इसने अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट दिया है। रेस्तरां, पब, मल्टीप्लेक्स, फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म और क्रिक कॉमर्स कंपनियां इस ऐतिहासिक मैच से ताबड़तोड़ कारोबार की उम्मीद कर रही हैं। कारोबार में भारी इजाफे की संभावना फुटबॉल प्रेमी इस महामुकाबले को बड़े पर्दे पर या घर पर ही जश्न मनाते हुए देखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी उम्मीद में, विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसाय इस बढ़ी हुई मांग का फायदा उठाने की तैयारी में जुट गए हैं। सेमी-फाइनल में अच्छी भीड़ देखने के बाद मल्टीप्लेक्स संचालक फाइनल के लिए रिकॉर्ड दर्शक संख्या की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं रेस्तरां और बार अपने ग्राहकों की संख्या में भारी इजाफे के लिए कमर कस चुके हैं, खासकर उन शहरों में जहां खुलने के समय में ढील दी गई है। क्रिक कॉमर्स और फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म भी इस देर रात के उत्साह को भुनाने के लिए ग्राहकों को भारी छूट और आकर्षक सौगातें दे रहे हैं। विज्ञापन दरों में उछाल और क्षेत्रीय लाभ इस बढ़े हुए उत्साह का असर विज्ञापन पर होने वाले खर्च में भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उद्योग सूत्रों के अनुसार फाइनल के लिए विज्ञापन की दरें टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों के दौरान 10-सेकंड के स्पॉट के लिए 2.5 लाख रुपये से बढ़कर दस गुना 25 लाख रुपये तक पहुंच गई हैं। झ

हालांकि, ये दरें अभी भी क्रिकेट विश्व कप के शुरुआती मैचों से कम हैं। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) को उम्मीद है कि फीफा विश्व कप फाइनल रेस्तरां को बेहतरीन कारोबार का मौका देगा। हैदराबाद और बेंगलुरु को सर्वाधिक फायदा होने की संभावना है, क्योंकि इन राज्यों में रेस्तरां और पब के खुलने का समय बढ़ा दिया गया है।

इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा वीएक्स2 प्लस का नया संस्करण पेश

नई दिल्ली ।

भारतीय बाजार में हीरो विडा ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा वीएक्स2 प्लस का एक नया संस्करण पेश किया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर का यह नया मॉडल, पहले से उपलब्ध 3.4 किलोवाट-घंटा संस्करण की तुलना में काफी अधिक ड्राइविंग रेंज प्रदान करता है। नए विडा वीएक्स2 प्लस की एक्स-शोरूम कीमत नई दिल्ली में 1.44 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जो इसे लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। इस नए संस्करण में दो हटाई जा सकने वाली 2.2 किलोवाट-घंटा बैटरियां दी गई हैं, जिनकी कुल क्षमता 4.4 किलोवाट-घंटा है। कंपनी का दावा है कि यह ईवी स्कूटर एक बार पूर्ण चार्ज होने पर 187 किलोमीटर की आईडीसी प्रमाणित रेंज प्रदान कर सकता है, जो इसके मौजूदा छोटे बैटरी पैक वाले मॉडल की 146 किलोमीटर की रेंज से काफी बेहतर है। चार्जिंग के लिए, इसके साथ 1 किलोवाट क्षमता वाला पोर्टेबल चार्जर मिलता है, जिससे बैटरी को शून्य से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 3 घंटे 17 मिनट और पूर्ण चार्ज होने में करीब 5 घंटे 8 मिनट का समय लगता है। डीसी फास्ट चार्जिंग की सुविधा का उपयोग करने पर, बैटरी केवल 65 मिनट में 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है, और हीरो के 6,000 से अधिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन देशभर में उपलब्ध हैं।

वीएक्स2 प्लस में पहले की तरह 6 किलोवाट की मोटर दी गई है, जो 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करती है और इसकी अधिकतम गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है।

इसमें ईको, राइड और स्पोर्ट जैसे तीन राइडिंग मोड के साथ-साथ ओवरटेकिंग के लिए बूस्ट सुविधा भी मिलती है। स्कूटर में 4.3 इंच की टीएफटी स्क्रीन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और मोड़-दर-मोड़ दिशा-निर्देशन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल हैं।

रिलायंस के ओ2सी का बंपर मुनाफा, राजस्व 30 फीसदी बढ़ा

कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और बेहतर मार्जिन रहे प्रमुख कारण

मुंबई ।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के ऑयल-टु-केमिकल्स (ओ2सी) कारोबार ने जून 2026 तिमाही में जोरदार प्रदर्शन किया है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और मजबूत मार्जिन के दम पर कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 30 फीसदी बढ़कर 2,01,803 करोड़ रुपये और एबिटा 17 फीसदी बढ़कर 17,010 करोड़ रुपये हो गया। कच्चे तेल की कीमतें, जो होरमुज स्ट्रेट बंद होने से बढ़कर 104.5 डॉलर प्रति बैरल हो गईं, इस राजस्व वृद्धि का मुख्य कारण रहीं। बेहतर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल क्रैक और डाउनस्ट्रीम मार्जिन ने एबिटा में बढ़ोतरी में योगदान दिया। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वैश्विक बाधाओं और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों के बावजूद इसे शानदार प्रदर्शन बताया। हालांकि, महंगे फीडस्टॉक की खरीद, निर्धारित रखरखाव और बढ़ती माल ढुलाई व बीमा लागत ने मार्जिन पर दबाव डाला। घरेलू बाजार में, आरआईएल ने ईंधन कीमतें स्थिर रखीं और एलपीजी उत्पादन बढ़ाया, जिससे बिक्री में नुकसान हुआ। डीजल, मोटर स्पिरिट (एमएस) और एटीएफ पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की पुनः बहाली ने भी मार्जिन को प्रभावित किया।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सीकैप फंड ने 5 साल में दोगुना किया निवेशकों का पैसा

एकमुश्त निवेश और एसआईपी दोनों में बंपर मुनाफा; जानें क्या है इस स्कीम की खास रणनीति

नई दिल्ली ।

जो निवेशक बिना अधिक जोखिम उठाए अपने पैसों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सीकैप फंड एक आकर्षक विकल्प बनकर उभरा है। एक विश्लेषण के अनुसार, इस स्कीम ने पिछले 5 साल के दौरान (जुलाई 2021 से जून 2026 तक) 14 फीसदी तक का सालाना चक्रवृद्धि रिटर्न दिया है, जिससे निवेशकों का पैसा लगभग दोगुना हो जाता है। यह फंड लम्पसम और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) दोनों तरीकों से शानदार रिटर्न देने में सक्षम रहा है।यह स्कीम लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में एकसाथ निवेश करती है, जिससे जोखिम को संतुलित रखते हुए बेहतर रिटर्न हासिल किया जा सके। आंकड़ों के मुताबिक यदि 17 जुलाई, 2021 को इस स्कीम में 10 लाख रुपये का एकमुश्त निवेश किया गया होता, तो 30 जून, 2026 तक उसकी कीमत बढ़कर करीब 19.61 लाख रुपये हो जाती, जो 14.55 फीसदी का चक्रवृद्धि रिटर्न दर्शाता है। यह स्कीम के बेंचमार्क के 11.88 फीसदी रिटर्न से कहीं बेहतर है। एसआईपी निवेशकों के लिए भी यह फंड काफी फायदेमंद साबित हुआ है। स्कीम शुरू होने के बाद से यदि हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी 30 जून, 2026 तक की गई होती, तो कुल 6 लाख रुपये के निवेश पर 8.47 लाख रुपये मिलते। यह 13.83 फीसदी के मजबूत सीएजीआर को दर्शाता है, जबकि इसके बेंचमार्क ने 10.43 फीसदी का रिटर्न दिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएएमसी के एक अधिकारी के अनुसार, स्कीम का उद्देश्य ऐसे पोर्टफोलियो बनाना है जो बाजार में गिरावट के दौरान भी तेजी से रिकवर कर सकें। यह ग्रोथ से वैल्यू बनती है के सिद्धांत पर काम करती है, जिसका फोकस लंबी अवधि की वृद्धि क्षमता वाले व्यवसायों में निवेश पर रहता है।

एआई से डरे नहीं युवा, भारतीय आईटी को मिलेंगे नए अवसर- आनंद महिंद्रा

भारत को उपभोक्ता नहीं, बल्कि एआई का निर्माता बनना होगा

नई दिल्ली ।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी टेक महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने आर्टिफिशयल इंटेलीजेंस (एआई) को लेकर भारतीय आईटी सेवा उद्योग में व्याप्त आशंकाओं को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि एआई इस क्षेत्र की भूमिका को खत्म नहीं करेगा, बल्कि समय के साथ इसे और महत्वपूर्ण बनाएगा। युवाओं को एआई से घबराने के बजाय तालमेल बैठाने की सलाह दी गई है। टेक महिंद्रा की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में आनंद महिंद्रा ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में एआई रोजगार के कई नए अवसर पैदा करेगा और मौजूदा नौकरियों को बेहतर बनाएगा। उन्होंने जोर दिया कि भारत केवल बाहर विकसित प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि एआई के क्षेत्र में निर्माता और आकार देने वाला भी बनना होगा। परम सुपरकंप्यूटर का उदाहरण देते हुए उन्होंने स्वदेशी नवाचार और संप्रभु एआई के विकास में घरेलू क्षमता व आत्मनिर्भरता पर बल दिया।

जून में महिंद्रा एक्सयूवी 400 ईवी की कुल 31 यूनिट बिकीं

नईदिल्ली।

महिंद्रा की एक्सयूवी 400 ईवी को भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में जून 2026 में बड़ा झटका लगा है। बिक्री के जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने इस मॉडल की केवल 31 इकाइयों की बिक्री दर्ज की गई, जो जून 2025 में बेची गई 231 इकाइयों की तुलना में लगभग 87 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्शाती है। इस वजह से कंपनी के लिए एक्सयूवी 400 ईवी की कम बिक्री चिंता का विषय बन गई है। एक्सयूवी 400 ईवी का डिजाइन आधुनिक और आकर्षक है, जिसमें बंद ग्रिल और महिंद्रा का तांबे जैसी आभा वाला प्रतीक चिन्ह इसे अलग पहचान देता है। इसके केबिन में 10.25 इंच का स्पर्श आधारित सूचना एवं मनोरंजन तंत्र, पूर्णतः डिजिटल चालक सूचना पटल, बिना तार के एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ-साथ बिना तार का मोबाइल चार्जर जैसी कई प्रीमियम सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी दो बैटरी विकल्पों में आती है- एक 34.5 किलोवाट-घंटा और दूसरी 39.4 किलोवाट-घंटा क्षमता के साथ। कंपनी के अनुसार, बड़ा बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर 456 किलोमीटर तक की आईडीसी प्रमाणित रेंज प्रदान करता है, जबकि छोटा पैक 375 किलोमीटर तक की रेंज देता है। यह ईवी कार 8.3 सेकंड में शून्य से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और लगभग 50 मिनट में शून्य से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है।

नाबालिग ने लिव-इन पार्टनर को गोली मारी, परिवार की मदद से दफनाया

बेंगलुरु (एजेंसी)। कोडीहल्ली थाना क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज़ आपराधिक मामला सामने आया है, जहाँ एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़के ने अपनी लिव-इन पार्टनर, जो कि खुद भी नाबालिग थी, की गोली मारकर हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद, हत्या को छिपाने के लिए उसने अपने भाई और चाचा की मदद से शव को दफना दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नाबालिग लड़के के साथ-साथ उसके भाई और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे इस नृशंस अपराध का पर्दाफाश हुआ। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी के चाचा ने अपने दोस्तों को इस हत्या के बारे में बता दिया। मामला चर्चा में आया और धीरे धीरे मृतिका के परिजनों तक पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने जांच और पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस के अनुसार, यह वारदात 10 जुलाई को कोडीहल्ली थाना क्षेत्र के कैम्पलानाथ गांव में हुई थी। बताया जाता है कि आरोपी लड़के ने अपनी 16 वर्षीय गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया पर किसी दूसरे लड़के के साथ मैसेज पर बात करते हुए देख लिया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई और नाबालिग ने गुस्से में आकर लड़की के साथ मारपीट की। क्रोध में अंधे होकर उसने घर में रखा एक पुराना देसी कट्टा (हथियार) निकाला और अपनी गर्लफ्रेंड पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लड़की किसी दूसरे गांव की रहने वाली थी और अपने माता-पिता से दूर रहकर इस लड़के के साथ रह रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक, जांच अधिकारियों ने बताया कि हत्या के बाद नाबालिग लड़का घबरा गया और उसने अपने भाई व चाचा को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद, तीनों ने मिलकर लड़की के शव को दफना दिया ताकि पुलिस और आम लोगों की नज़रों से इस घिनौने जुर्म को छिपाया जा सके। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों नाबालिगों की दोस्ती करीब दो महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए ही हुई थी। पिछले एक महीने से लड़की आरोपी लड़के के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। लड़की ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने माता-पिता से झूठ कहा था कि वह अपनी एक सहेली के साथ रह रही है, इसलिए परिवार ने भी उस पर ज्यादा सवाल नहीं किए थे। वहीं, लड़के के परिवार को भी पता था कि लड़की उसके साथ रह रही है, लेकिन उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं जताई थी। फिलहाल कोडीहल्ली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

न्यू टाउन में किराए के कमरे में क्रूड बम धमाका, सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन स्थित राजारहाट इलाके में किराए के कमरे में हुए संदिग्ध क्रूड बम विस्फोट से हड़कंप मच गया। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ और आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है, जिसमें कुछ संदिग्ध लोग एक बैग छोड़कर जाते दिख रहे हैं। पुलिस ने मौके से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की है और दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। पुलिस के अनुसार, साउथ नारायणपुर इलाके में सुपारी के बागान के भीतर बने एक ग्राउंड फ्लोर के कमरे में यह धमाका हुआ। यह कमरा हाल ही में कामारहाटी के एक व्यक्ति ने किराए पर लिया था। लोगों ने बताया कि दो व्यक्ति एक बैग लेकर कमरे में आए, उस अंदर छोड़ा और कुछ ही मिनटों बाद तेज धमाका हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि दो पड़ोसी कमरे भी क्षतिग्रस्त हो गए और इलाके में अफरा-तफरी मच गई। धमाके में कमरे के अंदर मौजूद एक व्यक्ति घायल हो गया, उस लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना देने के बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घायल की हालत फिलहाल स्थिर है। नारायणपुर थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस को बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मिली है, जिससे आशंका है कि कमरे का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री तैयार करने या छिपाने के लिए हो रहा था। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। पुलिस ने मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन लोगों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने कथित तौर पर बैग कमरे में रखा था।

ईवी नीति से घबराएं नहीं लोग, चरणबद्ध लागू होगी : सीएम रेखा गुप्ता

-1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो का पंजीकरण

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को लेकर आम जनता में फैली चिंताओं को दूर कर स्पष्ट किया है कि पेट्रोल और डीजल वाहन मालिकों को घबराने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह नीति अचानक लागू नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा ताकि किसी पर भी अनावश्यक बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समझाया कि कोई भी बड़ी व्यवस्था एकाएक नहीं बदलती, बल्कि व्यवस्था को आकार लेने में समय और कई साल लगते हैं। इसी सिद्धांत पर चलते हुए, ईवी नीति को इस तरह से तैयार किया गया है कि लोग धीरे-धीरे इस बदलाव को अपनाएं और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने साफ किया कि जिनके पास पहले से पेट्रोल और डीजल वाहन हैं, वे अपनी गाड़ियों का उपयोग उनकी वैध अवधि समाप्त होने तक बिना किसी रोक-टोक के कर सकते हैं। जनता को इस विषय पर किसी भी तरह की चिंता या भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा ने नीति के महत्वपूर्ण चरणों का उल्लेख कर बताया कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो का पंजीकरण होगा। इसका अर्थ है कि नए ऑटो खरीदने वालों को इलेक्ट्रिक विकल्प ही चुनना होगा, जबकि मौजूदा पेट्रोल-डीजल ऑटो अपनी निर्धारित अवधि तक चलते रहने वाले है। इसी क्रम में, अप्रैल 2028 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए नई पंजीकरण व्यवस्था लागू होगी, जिसमें नए टू-व्हीलर केवल इलेक्ट्रिक होगा। हालांकि, पुराने पेट्रोल या डीजल दोपहिया वाहन भी अपनी वैध समय-सीमा तक उपयोग किए जा सकते है। रेखा गुप्ता ने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के प्रदूषण को कम करना और शहर को स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ाना है, न कि किसी को परेशान करना। उन्होंने कहा कि यदि इसतरह के स्पष्ट और चरणबद्ध नियम नहीं लागू किए जाते हैं, तब सरकार द्वारा किया जा रहा करीब 15,000 करोड़ रुपये का निवेश भी पूरी तरह प्रभावी नहीं होगा। दिल्ली सरकार का लक्ष्य जनता को बेहतर सुविधाएं देना है ताकि वे स्वयं इस पर्यावरणीय बदलाव का हिस्सा बनें।

वांगचुक के अनशन को मिला विपक्ष का साथ, तेज होगा आंदोलन

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार जारी है। जंतर-मंतर पर चल रहा उनका यह आंदोलन अब 21वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इतने लंबे समय से उपवास पर रहने के कारण उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है और बताया जा रहा है कि इस दौरान उनका वजन लगभग 10 किलोग्राम तक कम हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर चिकित्सकों की एक विशेष टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है।

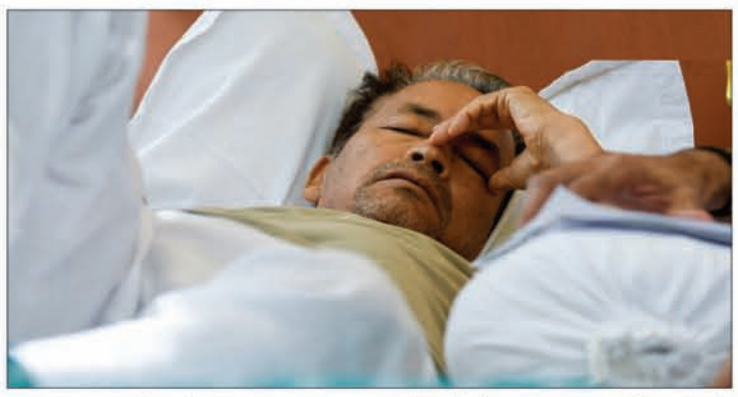

इस बीच, शुरुआत में इस आंदोलन से थोड़ी दूरी बनाए रखने वाली कांग्रेस अब खुलकर सोनम वांगचुक के समर्थन में सामने आ गई है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता जता चुके हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जंतर-मंतर पर वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने वहां मौजूद आंदोलनकारियों से बातचीत की और वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताते हुए उनसे अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने उन अन्य प्रदर्शनकारियों से भी चर्चा की जो परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता और बड़े सुधारों की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के इस बदले हुए रुख की काफी चर्चा हो रही है, जिसके पीछे वर्ष 1984 की एक ऐतिहासिक घटना को मुख्य कारण माना जा रहा है। उस समय लद्दाख में अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांगयाल एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं लेह पहुंची थीं और उनसे मुलाकात कर मांगों पर गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया था। हालांकि उसी वर्ष इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, लेकिन वह आंदोलन जारी रहा और अंततः वर्ष 1989 में केंद्र सरकार ने लद्दाख के आठ समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया। सोनम वांगयाल क्षेत्र की राजनीति में काफी सक्रिय थे और उन्होंने विधायक, विधान परिषद सदस्य तथा राज्य सरकार में मंत्री के रूप में सेवाएं दी थीं। सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में हुई संसदीय दल की बैठक में वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने वर्ष 1984 की इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की याद दिलाई, जिसके बाद पार्टी ने आंदोलन को आधिकारिक तौर पर समर्थन देने का निर्णय लिया। शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर लंबे समय से सक्रिय सोनम वांगचुक ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आगामी 20 जुलाई से संसद मार्च का भी आह्वान किया है।

लॉरेंस के भाई आरजू बिश्नोई ने दी अभिनेता आमिर खान को धमकी

मुंबई (एजेंसी) बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सलमान खान के बाद अब आमिर खान, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। आमिर खान को बिश्नोई गैंग ने धमकी दी है। बताया जा रहा है कि आमिर को धमकी देना वाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई आरजू बिश्नोई है, जिसका ऑडियो भी सामने आया है।

आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और ऑडियो शेयर करके आमिर खान को धमकी दी है। हालांकि, हम इस सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। जानकारी के मुताबिक पोस्ट में लिखा है- जय श्री राम, जय सीता राम। मैं आरजू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई। ये जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हमारे देश में लव जिहाद के नाम पर आमिर खान जैसे लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब बहुत जल्द दिया जाएगा। ये चीज हमारे सनातन धर्म में और देश के खिलाफ है। हमारा, हमारे भाई-बहनों और देशवासियों से वादा है कि जो भी इस घटिया हरकत को बढ़ावा देगा, उसको हम अपने तरीके से जवाब देंगे। ये जो स्टारडम के नाम पर इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी हम सांसें दबा लेंगे। आमिर खान को मिली धमकी में लव जिहाद का जिक्र किया गया है, जिससे इतना साफ है कि बिश्नोई गैंग, आमिर खान की तीसरी शादी से नाराज है। बता दें कि आमिर ने जबसे गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी करके घर बसाया है, तभी से वह मुश्किलों में हैं। आमिर की तीसरी शादी का जमकर विरोध किया जा रहा है। दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ आमिर की शादी को लव जिहाद माना जा रहा है। दूसरे धर्म की महिलाओं के साथ शादी करने पर आमिर खान को लेकर फतवा भी जारी हो गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने भी आमिर को लव जिहाद के ब्रांड एंबेसडर का टैग दिया है। अब आमिर को बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिलने पर फैंस की चिंता बढ़ गई है।

सीता के पति, नीता के पति वाले बयान पर कुणाल कामरा को भेजा लीगल नोटिस

-नोटिस में माफी मांगने और विवादित बयान वाले वीडियो हटाने की मांग

नई दिल्ली(एजेंसी)। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा शुरू किए गए आंदोलन में शामिल सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे थे। 21वें दिन प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वांगचुक को धरना स्थल से जबरन हटा दिया गया। इससे पहले सोनम वांगचुक के इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा भी जंतर-मंतर पहुंचे थे। आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कामरा ने कुछ ऐसी टिप्पणियां कीं जिससे अब एक नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुणाल कामरा द्वारा दिए गए सीता के पति, नीता के पति वाले बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि ईश्वर एक पवित्र भावना है। हमारे आराध्य देव का नाम इस तरह बदनाम नहीं किया जा सकता है। भगवान का अनादर हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस नोटिस के जरिए कामरा से माफी मांगने और विवादित बयान वाले वीडियो को हटाने की मांग की गई है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी कामरा को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

बता दें आंदोलन के मंच से छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए कुणाल कामरा ने कहा कि मैं छात्रों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई मोदी समर्थक या बीजेपी का वोटर मिले तो उससे बहस करने के बजाय बहुत सहजता से बात करें। हमें मरीज का नहीं, बल्कि बीमारी का इलाज करना है। अगर कोई अंधभक्त यह कहे कि मोदीजी ने जो किया, सही किया तो अपना समय बर्बाद न करें। वहां से चुपचाप निकल जाएं। इस सरकार को कोई शर्म नहीं है। कामरा ने आगे कहा, आप लोग छात्र हैं, कुछ किसान हैं, कुछ बेरोजगार हैं। मैं आप सभी की तरफ से भारत के मुख्य न्यायाधीश का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने ही इस आंदोलन को शुरू करने की पहली ईंट रखी थी।

महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़, एनडीए में विलय को टाल रहीं सुनेत्रा

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर गरमागरमी देखी जा रही है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के कुनबे को बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विलय की पुरजोर कोशिश कर रही है। हालांकि, इस विलय के प्रयासों में सबसे बड़ा रोड़ा सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार बन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, सुनेत्रा और पार्थ को यह आशंका है कि यदि दोनों एनसीपी गुट एक हो जाते हैं, तो पार्टी की कमान फिर से शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले के हाथों में चली जाएगी, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है। फिलहाल, एनसीपी एनडीए का हिस्सा है जबकि एनसीपी (एसपी) विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है।

इस राजनीतिक उठापटक के बीच, सुनेत्रा पवार के करीबी नेताओं का मानना है कि उनकी पार्टी के कुछ सदस्य दोनों गुटों के विलय के पक्ष में हैं। लेकिन सुनेत्रा पवार, जो एनसीपी की अध्यक्ष हैं, और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार इस कदम का

लगातार विरोध कर रहे हैं। वे किसी भी कीमत पर शरद पवार और सुप्रिया सुले को पार्टी का नेतृत्व वापस सौंपने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में, गुरुवार शाम को पार्थ पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इधर, सियासी गलियारों में एक और बड़ी चर्चा ने जोर पकड़ा है कि शरद पवार खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ हाथ मिला सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि यह गठबंधन होता है, तो उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल को महाराष्ट्र के वित्त मंत्रालय का प्रभार सौंपा जा सकता है। यह मंत्रालय पहले दिवंगत अजीत पवार के पास था और इसे राज्य सरकार में एक बेहद महत्वपूर्ण पद माना जाता है। इस संभावित कदम से राज्य सरकार के भीतर सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है।

हाल के दिनों में जयंत पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से दो दिन पहले भेंट की थी, जबकि गुरुवार को उन्होंने और पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड ने मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात की। आव्हाड और शिंदे के बीच इस मुलाकात को राजनीतिक विश्लेषक काफी अहम मान रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही नेता ठाणे जिले से आते हैं और पारंपरिक रूप से एक-दूसरे के राजनीतिक विरोधी रहे हैं। इन मुलाकातों से साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। पार्थ पवार ने अपनी एक बैठक में यह भी सवाल उठाया कि एनसीपी नेताओं और मुख्यमंत्री के बीच चल रही गोपनीय चर्चाओं की जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि, देवेंद्र फडणवीस ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि वे सीधे सुनेत्रा पवार से इस बारे में बात करेंगे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि यदि एनसीपी (एसपी) और एनसीपी का विलय होता है, तो सुनेत्रा पवार एक शर्त रख सकती हैं कि उन्हें उपमुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रखा जाए और पार्टी की कमान भी उनके हाथों में ही रहे। यह सारी कवायद महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी बड़े बदलावों का संकेत दे रही है।

ममता के भतीजे अभिषेक के पांच मंजिला अवैध आफिस पर चला बुलडोजर

कोलकाता (एजेंसी)। सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के अवैध रूप से निर्मित कार्यालय पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस पांच मंजिला दफ्तर को गिराने के लिए तीन मशीनें लगाई गई। अभिषेक बनर्जी का यह दफ्तर अमताला-बारुईपुर रोड पर स्थित है। प्रशासन ने इस इमारत को तोड़ने के लिए पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन इस पर अभिषक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद शनिवार को प्रशासन ने इस इमारत को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस को अवैध निर्माण के आरोप में तोड़े जाने की कार्रवाई शुरू होने के बाद राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इस इमारत के सामने जैसे ही सुबह बुलडोजर पहुंचा, लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और टीएमसी कार्यकर्ता भी यहां जमा हो गए। स्थिति तनावपूर्ण होता देख प्रशासन को सुरक्षाकर्मी बुलाने पड़े। सुरक्षा के लिहाज से यहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इससे पहले प्रशासन ने एक नोटिस चिपकाकर आरोप लगाया था कि यह इमारत बिना मंजूरी के बनाई गई थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से यह कार्यालय बंद था। जिला प्रशासन का दावा है कि यह कार्यालय अवैध रूप से बनाया गया था। कार्यालय के निर्माण से संबंधित कोई वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

देश के 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी, लोगों को दी सलाह

तेज हवाओं से पेड़, बिजली के खंभे और खड़ी फ़सलों को पहुंच सकता है नुकसान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां तेज होने के साथ ही भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। आईएमडी के मुताबिक यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में तेज हवाओं और आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। तेज हवाओं से पेड़, बिजली के खंभे और खड़ी फ़सलों को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि कई इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा है।

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे आंधी-तूफान में घर के अंदर ही रहें, पेड़ों के नीचे न जाएं। खराब मौसम से प्रभावित इलाकों में परिवहन और बिजली आपूर्ति में रुकावट की संभावना को देखते हुए लोगों को भी सावधान किया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित मौसम केंद्र ने 19 से 23 जुलाई के बीच कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट इसलिए जारी किया गया है, क्योंकि शनिवार से दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ-साथ इस इलाके में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे पूरे राज्य में व्यापक बारिश

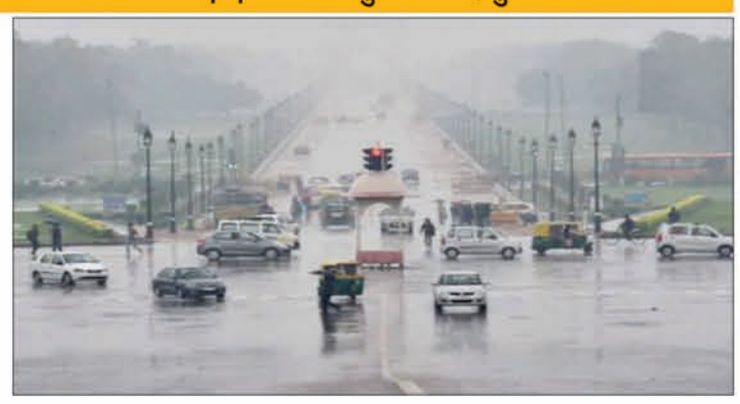

होगी।

मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि शनिवार को मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने लोगों और पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील की है, खासकर उन इलाकों में जहां भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा ज्यादा है। इस बीच, आईएमडी ने जम्मू-कश्मीर के लिए भी चेतावनी जारी की है। इसमें अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के साथ-साथ अचानक बाढ़, भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई गई है। विभाग ने लोगों को शनिवार रात, रविवार सुबह और 20 से 22 जुलाई के बीच बरतने की सलाह दी है, क्योंकि इस दौरान मौसम के हालात खराब रहने की उम्मीद है। आईएमडी ने प्रभावित इलाकों के लोगों से मौसम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और सलाह पर बारीकी से नजर रखने को कहा है, क्योंकि मौसम की स्थिति तेजी से बदल सकती है।

आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी कोविड19 की दस्तक, 21 मामले आए सामने

-डॉक्टर बोले-कोविड अब इन्फ्लूएंजा की तरह हमारे बीच रहने वाला है, सावधानी बरतें

पुणे (एजेंसी)। कोरोना वायरस ने करीब तीन साल बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से इसकी दस्तक सुनाई दे रही है। राज्य में विशेषकर पुणे शहर में पिछले 10 दिनों में कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामले हल्के लक्षणों वाले हैं और स्वास्थ्य विभाग या विशेषज्ञों को फिलहाल किसी नई लहर का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट में राज्य स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में इस साल अब तक कोविड-19 के 48 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। करीब तीन सालों तक यह वायरस रडार से बाहर रहा, लेकिन साल 2026 में इसके मामलों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस साल जनवरी में 3, फरवरी में 1, जून में 11 और अब तक जुलाई में 21 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक ज्यादातर पॉजिटिव मामले नियमित कोविड टेस्टिंग के दौरान नहीं मिल रहे हैं। ये मामले तब सामने आ रहे हैं जब मरीज किसी अन्य बीमारी के लिए डॉक्टर की सलाह पर जांच करा रहे हैं या फिर किसी सर्जरी से पहले उनका प्री-ऑपरेटिव फिटनेस टेस्ट किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस अब इन्फ्लूएंजा की तरह बर्ताव कर रहा है। लोगों में इम्युनिटी कम होने और नए वेरिएंट के उभरने के कारण हर एक-दो साल में इसके मामलों में इस तरह का उछाल आना स्वाभाविक है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने बताया कि 2023 के बाद यह पहली बार है जब कोविड के मामलों में इतनी बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 8 से 10 दिनों में कोविड और इन्फ्लूएंजा दोनों के मरीज बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा संक्रमण ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी हल्का है। मरीजों में आमतौर पर खांसी, जुकाम, गले में खराश और थकान जैसे लक्षण दिख रहे हैं, जो 3 से 5 दिनों तक रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समुदाय में संक्रमण का वास्तविक आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हल्के लक्षण वाले बहुत से लोग टेस्ट ही नहीं कराते हैं। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि कोविड अब इन्फ्लूएंजा की तरह हमारे बीच ही रहने वाला है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें और लापरवाही न करें। डॉक्टरों का कहना है कि मौजूदा स्थिति किसी कोविड लहर जैसी बिल्कुल नहीं है। पहले टेस्टिंग कम होने की वजह से छिटपुट मामलों पर ध्यान नहीं गया। अब चूंकि अन्य रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, इसलिए अस्पतालों में अपर रेस्पिरेटरी पैनल का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश में 26 जून से 16 जुलाई के बीच कोविड के 12 मामले सामने आए हैं, जिनमें से चार लोगों की मौत हुई है। अकेले कडप्पा जिले में कोरोना वायरस के आठ मामले दर्ज किए गए। गुंटूर जिले में दो मामले और विशाखापत्तनम व काकीनाडा जिलों में एक-एक मामला दर्ज किया गया। इन पांच लोगों के स्वाब के नमूने जांच के लिए पुणे स्थित नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजे गए थे।

राम मंदिर में भर्ती अनियमितताएं: चढ़ावा गिनने वाले 5 कर्मचारी जांच में फेल

अयोध्या(एजेंसी)। भव्य राम मंदिर के संचालन और वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार, राम मंदिर में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण नियमों की अनदेखी की गई है, विशेषकर उन पदों पर जहाँ भक्तों द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे की गिनती का संवेदनशील कार्य किया जाता है। अब यह पुष्टि हुई है कि ऐसे ही कुछ कर्मचारियों को बिना उचित पुलिस सत्यापन के ही नौकरी पर रखा गया था। हालिया जांच में ऐसे पांच कर्मचारी सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त कर दिया गया। यह खुलासा और भी चौंकाने वाला है क्योंकि ये कर्मचारी पिछले दो वर्षों से बिना किसी उचित पृष्ठभूमि जांच के इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहे थे।

जांच अधिकारियों को निगरानी, संचालन और भर्ती जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं में भरपूर हीलाहवाली के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, जिसका प्रारंभिक रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है। बीते कुछ दिनों की कार्रवाई पर नजर डालें तो गणना से जुड़े कर्मचारियों के सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से जारी है, और इसी क्रम में ये अनियमितताएं सामने आई हैं। गणना कक्ष के कर्मचारियों की संख्या में भी अस्थिरता देखी गई है। कुछ समय पहले वेतन कम होने और काम के घंटे बढ़ने से नाराज होकर 23 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या घटकर 13 रह गई। हालांकि, उनमें से दो बाद में काम पर लौट आए, जिससे संख्या 15 हो गई। लेकिन इस बीच, पहले से कार्यरत दो कर्मचारियों पर पुलिस केस होने की जानकारी मिलने पर उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, शेष कर्मचारियों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होने पर तीन और कर्मचारी जांच में फेल हो गए। इस तरह, वर्तमान में केवल 12 कर्मचारी ही नोट और सिक्कों की गिनती का कार्य कर रहे हैं। कई अन्य कर्मचारी भी कार्रवाई की जद में हैं और उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। सावन मेले से पहले गणना कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए, निजी भर्ती एजेंसी उन पूर्व कर्मचारियों को प्राथमिकता दे रही है जिन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनके पास कार्य का अनुभव है। हालांकि, अब इन कर्मचारियों का भी कड़ा पुलिस सत्यापन कराया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया में भी कई ऐसे कर्मचारी पाए गए हैं जिनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज हैं। प्रबंधन ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में केवल सत्यापन में पास होने वाले लोगों को ही नियुक्त किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से मानकों के अनुरूप हो और मंदिर की पवित्रता तथा वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे।